Discover your divinity with us
A/C Showroom
ज्ञान गंगा ॐ मूर्ति माला केन्द्र
उजाला भवन स्टेशन रोड, दुर्ग
0788-4030383, 3293199
भगवान के वस्त्र, श्रृंगार
मूर्तियां एवं समस्त
पूजन सामग्री
संगमरमर व पीतल की
मूर्तियां राशि रत्न
एवं उपरत्न उपलब्ध

राष्ट्र एवं राज्य के प्रगति पथ पर...

समय दर्शन

रायपुर एवं दुर्ग से प्रकाशित

ESTD : Since 2011

संस्थापक : स्व. श्रीमती निलिमा खड़तकर

निष्पक्ष निर्भीक ख़बरों के साथ

श्री
दुर्ग शहर में
सुप्रसिद्ध
ज्योतिषाचार्य

माँ दुर्गा उपासक मां बगुलामुखी, माँ कामख्या, माँ भद्रकाली, माँ शतचंडी की असीम कृपा साधना द्वारा समस्त समस्याओं का मार्ग दर्शन हेतु
पं. एम.पी. शर्मा/
मो. 8109922001
फीस 251/- मात्र
पताः- श्री दुर्गा ज्योतिष कार्यालय
सिकोला भाठा, सब्जी मार्केट के
सामने, धमधा नाका, दुर्ग

वर्ष 15, अंक 54 पृष्ठ 8, मूल्य 3.00 रूपये दुर्ग, मंगलवार 30 दिसंबर 2025 www.samaydarshan.in

संक्षिप्त समाचार

भारत से ओमान रवाना होगा नौसेना का इंजन रहित जहाज आईएनएसवी कौंडिन्य

नईदिल्ली। भारतीय नौसेना का सबसे अनोखा जहाज आईएनएसवी कौंडिन्य सोमवार को गुजरात के पोरबंदर से ओमान के मस्कट के लिए रवाना होगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसे हरी झंडी दिखाएंगे। यह इस जहाज की पहला समुद्री यात्रा होगी। यह जहाज दो हफ्तों में मस्कट यात्रा पूरी करेगा और उसके बाद इंडोनेशिया की राजधानी बाली के लिए रवाना होगा। यह वही मार्ग है जिससे होकर हजारों साल पहले व्यापार हुआ करता था। आइए इस जहाज की खासियत जानते हैं।

इस यात्रा का उद्देश्य भारत की प्राचीन समुद्री परंपराओं का परीक्षण करना है। इसका नाम प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय नाविक कौंडिन्य के नाम पर रखा गया है। कौंडिन्य प्राचीन भारत काल में भारत से दक्षिण-पूर्व एशिया तक समुद्री यात्रा करने के लिए जाने जाते थे। आधुनिक नौसैनिक जहाजों के विपरीत आईएनएसवी कौंडिन्य में कोई इंजन, धातु की कीलें या आधुनिक प्रणोदन प्रणाली नहीं है। भारत इस यात्रा से दुनिया को देश की मेरीटाइम हेरिटेज से वाकिफ कराएगा।

आईएनएसवी कौंडिन्य पूरी तरह से हवा, पाल और 1,500 साल से भी अधिक पुरानी जहाज निर्माण पद्धति पर निर्भर है। यह एक सिलाईदार पाल वाला जहाज है जिसके निर्माण में 5वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली प्राचीन तकनीकों का उपयोग करके बनाया गया है। इसका डिजाइन मुख्य रूप से अजंता गुफा चित्रों में दिखाए गए जहाजों के साथ-साथ प्राचीन ग्रंथों और विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों पर आधारित है।

इस जहाज को सिला हुआ जहाज भी कहा जाता है क्योंकि इसके लकड़ी के तख्तों को लोहे की कीलों से जोड़ने के बजाय नारियल के रेशे (कॉयर) की रस्सियों से सिला जाता है। जहाज के बाहरी आवरण को सील करने और उसे समुद्र में चलने योग्य बनाने के लिए प्राकृतिक राल, कपास और तेल का उपयोग किया जाता है। बड़ी बात यह है कि आईएनएसवी कौंडिन्य भारतीय नौसेना से संबंधित होने के बाद भी एक युद्धपोत नहीं है।

आईएनएसवी कौंडिन्य जहाज का आकार लगभग 19.6 मीटर लंबा, 6.5 मीटर चौड़ा और लगभग 3.33 मीटर गहरा है। यह पूरी तरह से पाल से चलता है और इसमें लगभग 15 नाविकों का दल होता है। यह जहाज पारंपरिक भारतीय जहाज निर्माण तकनीक टंकाई पद्धति का अनुसरण करता है। इसमें पहले पतवार बनाई जाती और बाद में पसलियां जोड़ी जाती हैं। इसकी लचीली संरचना जहाज को दबाव में टूटने के बजाय तेज लहरों को सहन करने में मदद करती है।

यह परियोजना जुलाई 2023 में संस्कृति मंत्रालय, भारतीय नौसेना और होडी इनोवेशन के बीच एक संयुक्त समझौते के माध्यम से शुरू हुई, जिसे संस्कृति मंत्रालय से वित्त पोषण मिला। केरल के पारंपरिक शिल्पकारों की एक टीम ने कुशल जहाज निर्माता बाबू शंकरन के नेतृत्व में जहाज को हाथ से तैयार किया है। कोई ब्लूप्रिंट उपलब्ध न होने के कारण भारतीय नौसेना ने दृश्य स्रोतों का उपयोग करके डिजाइन को दोबारा तैयार करने में सहायता की है। आईएनएसवी कौंडिन्य को फरवरी 2025 में लॉन्च किया गया था और मई में कर्नाटक के कारवार में इसे औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल कर लिया गया था। आईएनएसवी कौंडिन्य में भारत के समुद्री इतिहास से जुड़े कई सांस्कृतिक प्रतीक मौजूद हैं। इनमें गंडाभेरुंडा (कदंब वंश का दो सिर वाला बाज), पालों पर सूर्य के रूपांकन, सिंह याली (धनुष पर अंकित एक पौराणिक शेर की आकृति) और डेक पर हड़प्पा शैली का एक पत्थर का लंगर शामिल है।

भारत में ईसाइयों की तकलीफें खत्म हों: मिजोरम कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष

इंफाल। मिजोरम कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लाल थंजारा ने मांग की है कि भारत में ईसाइयों की तकलीफें खत्म हों। दुनिया भर में ईसाई खुशी से क्रिसमस मनाते हैं। यह बहुत शर्म की बात है कि भारत में भाजपा से जुड़े संगठन क्रिसमस सेलिब्रेशन पर हमला कर रहे हैं, उसे रोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि मिजोरम कांग्रेस कमेटी क्रिसमस की सजावट को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने और क्रिसमस कैरोल में हिंसक रुकावट डालने की कड़ी निंदा करती है। क्रिसमस सेलिब्रेशन में हिस्सा लेने पर बच्चों पर हमले की खबरें चौंकाने वाली हैं और किसी भी सभ्य समाज में इसे मंजूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी घटनाएं अकेली नहीं हैं। भाजपा शासित राज्यों में ये घटनाएं अधिक हो रही हैं। असम के नलबाड़ी जिले में, सेंट मैरी स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारियों को बर्बाद कर दिया गया, जिससे अल्पसंख्यकों की रक्षा करने और संविधान को बनाए रखने में भाजपा की नाकामी सामने आई है।

भारत संवैधानिक रूप से एक सेक्युलर देश है, फिर भी भाजपा के राज में सेक्युलरिज्म को सिस्टमैटिक तरीके से खत्म किया जा रहा है। अकेले 2024 में, ईसाइयों को जुल्म की 834 घटनाओं का सामना करना पड़ा।

हम हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के इच्छुक

उन्नाव रेप केसः सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत पर लगाई रोक

नईदिल्ली (एजेंसी)। उन्नाव रेप केस में सजायाफ्ता पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से जमानत देने और सजा निलंबित किए जाने खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्रीय जांच ब्यूरों (सीबीआई) ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सेंगर की जमानत को रद्द कर दिया है। कोर्ट कहा कि सेंगर को जमानत नहीं मिलनी चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की अवकाश पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, हम पाते हैं कि कानून के महत्वपूर्ण सवाल हैं, जिन पर विचार करने की जरूरत है। इस पर 14 दिन की नोटिस जारी की जाए। इसी तरह जवाब आने तक सेंगर की जमानत पर रोक लगाई जाती है। अपराध की प्रकृति के आधार पर जमानत मिलने के बाद भी सेंगर जेल से बाहर नहीं आ सकता है।सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने कहा कि यह मामला धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज है। सेंगर की जमानत आगे चलकर अन्य मामलों में नजीर बन सकती है। उन्होंने कहा कि पीड़िता की उम्र 16 वर्ष से कम थी। ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को निर्विवाद रूप से आईपीसी की धारा 376 के तहत दोषी ठहराया है, जिसमें न्यूनतम 20 वर्ष की सजा है। ऐसे में आरोपी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। एसजी मेहता की दलीलों पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, फिलहाल हम हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के इच्छुक हैं। आमतौर पर नियम यह है कि अगर व्यक्ति जेल से बाहर है तो कोर्ट उसकी आजादी नहीं छीनता, लेकिन इस मामले में स्थिति अलग है क्योंकि सेंगर दूसरे केस (पीड़िता के पिता की हत्या) में अभी भी जेल में है। सीजेआई ने कहा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से समझौते का कोई सवाल ही नहीं उठता। सेंगर फिलहाल जेल में ही रहेंगे। पीड़ित पक्ष के वकील हेमंत कुमार मौर्या ने कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूं। पीड़ित परिवार को लगा था कि आरोपी रिहा हो गया, तो उसकी गैंग उसके परिवार के बाकी सदस्यों को मार देगी। मैं पीड़ित के चाचा का वकील हूं। उनके चाचा को आर्थिक रूप से बर्बाद करने का दबाव चल रहा है। उनके परिवार के एक नाबालिग सदस्य को स्कूल से निकाल दिया है और अब उसे किसी स्कूल में प्रवेश नहीं मिल रहा। दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को सेंगर को सशर्त जमानत दी थी। जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने सेंगर की सजा को भी उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील लंबित रहने तक निलंबित कर दिया था। कोर्ट ने सेंगर को पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे में न जाने और जमानत अवधि में दिल्ली में ही रहने के आदेश दिए थे। इसी तरह शर्तों के उल्लंघन पर जमानत रद्द करने की चेतावनी दी थी। हाई कोर्ट ने माना था कि सेंगर के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(सी) के तहत अपराध नहीं बनता। कोर्ट ने कहा कि सेंगर को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376(2)(बी) के लिए लोक सेवक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

'आपका खराब रिकॉर्ड सब बयां कर रहा', भारत की पाकिस्तान को दो टूक; अल्पसंख्यकों पर दिया था ज्ञान

'आरोप-प्रत्यारोप से तथ्य नहीं छिप सकते' :विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली(एजेंसी)। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। अल्पसंख्यक नाबालिग लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन से लेकर ईशनिंदा के नाम पर पीट-पीटकर हत्या के मामले जगजाहिर हैं। इतना सब होने के बावजूद पाकिस्तान ने भारत में क्रिसमस पर अपवाद के तौर पर हुई तोड़फोड़ की खबरों पर ज्ञान देने की कोशिश की।

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान पर अब भारत सरकार ने पड़ोसी देश की सरकार को दो टूक सुना दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'हम उस देश की कथित टिप्पणियों को खारिज करते हैं जिसका इस मामले में बेहद खराब रिकॉर्ड खुद ही सब कुछ बयां करता है।'

विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है, 'विभिन्न धर्मों के अल्पसंख्यकों पर पाकिस्तान का भयावह और सुनियोजित उत्पीड़न एक सर्वविदित तथ्य है। किसी भी तरह के आरोप-प्रत्यारोप इसे छिपा नहीं सकते हैं।' भारत में क्रिसमस के दौरान हुई तोड़फोड़ की छिटपुट घटनाओं और भारत में तथाकथित तौर पर मुसलमानों के खिलाफहिंसा को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने जहर उगला था।

कश्मीर में 40 दिनों की भीषण सर्दी शुरू, लद्दाख में तापमान शून्य से 18 डिग्री नीचे

श्रीनगर (एजेंसी)। कश्मीर घाटी में 40 दिनों की भीषण सर्दी शुरू हो गई है, जिससे तापमान शून्य से नीचे चला गया है। इस कड़कड़ाती सर्दी को आम भाषा में चिल्लई कलां कहते हैं। हांड़ कंपाने वाली सर्दी 21-22 दिसंबर से शुरू हुई है, जो 40 दिनों तक चलेगी। इस बीच, लद्दाख में भी काफी ठंड पड़ रही है, जिससे यह देश का सबसे ठंडा क्षेत्र बन गया है। लद्दाख में तापमान लगातार गिर रहा है। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में सोनमर्ग का तापमान सबसे कम शून्य से 5.8 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है। विश्व प्रसिद्ध स्की रिसॉर्ट गुलमर्ग में भी तापमान शून्य से 4.2 और पहलगाम रिसॉर्ट में शून्य से 4.8 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में तापमान शून्य से 4.7, पुलवामा में शून्य से 4.3, श्रीनगर में शून्य से 2.6 और श्रीनगर हवाई अड्डे पर तापमान शून्य से 3.48 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

लद्दाख में इस समय सबसे ठंडा क्षेत्र है, जहां तापमान लगातार गिर रहा है। लेह शहर में न्यूनतम तापमान शून्य से 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कारगिल में यह शून्य से 9.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। द्रास इस क्षेत्र का सबसे ठंडा स्थान बना हुआ है, जहां तापमान शून्य से 18.1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि अगले कुछ दिनों में बर्फबारी ठंड बढ़ाएगी।

कश्मीर में चिल्लई कलां के पहले दिन गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों सहित ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हुई है। श्रीनगर स्थित मौसम विभाग का कहना है कि नए साल पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। उत्तरी और मध्य कश्मीर के कुछ मध्य और ऊंचे इलाकों में मध्यम बर्फबारी हो सकती है। इससे गुलमर्ग और पहलगाम जैसे क्षेत्रों समेत राज्य में पर्यटन को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

दिल्ली में कोहरे के कारण दृश्यता प्रभावित; 130 उड़ानें रद्द, एयरलाइंस ने चेतावनी जारी की

नईदिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में सोमवार को घने कोहरे के कारण दृश्यता घटकर 50 मीटर से नीचे पहुंच गई। दिल्ली में इसका सबसे ज्यादा असर उड़ानों पर पड़ा। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोमवार को 128 उड़ानें रद्द हुईं, जिनमें 64 आगमन और 64 प्रस्थान शामिल हैं, साथ ही 8 उड़ानों का मार्ग भी बदला गया है। इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट सहित कई एयरलाइनों ने खराब मौसम के कारण चेतावनी जारी की है।

इंडिगो की वेबसाइट के मुताबिक, सोमवार को खराब मौसम के कारण मुंबई, बेंगलुरु, कोचीन, जयपुर, अमृतसर, पटना, भोपाल, इंदौर समेत अन्य शहरों की करीब 80 उड़ानें रद्द हुई हैं। मंगलवार को एक उड़ान रद्द है। सुबह साढ़े 11 बजे इंडिगो ने एक्स पर बताया, दिल्ली और उत्तरी भारत के कई एयरपोर्ट पर अभी कोहरे का असर बना हुआ है, और दृश्यता में अभी पूरी तरह सुधार नहीं हुआ है। इसके चलते, उड़ान पर दोपहर तक कुछ देरी हो सकती है। दिल्ली हवाई अड्डा अधिकारियों ने बताया कि सोमवार सुबह हवाई अड्डे पर रनवे की दृश्यता 100-150 मीटर के बीच थी, जिससे हवाई यात्रा विशेष रूप से प्रभावित हुई।

बांग्लादेश में हिंदू परिवार के 5 घरों में आग लगाई :दरवाजे बाहर से बंद थे

लोग बाड़ काटकर घर से निकले; पांच संदिग्ध गिरफ्तार

ढाका (एजेंसी)। बांग्लादेश में हिंदू परिवारों के कम से कम पांच घरों में आग लगाने की घटना सामने आई है। यह घटना शनिवार, 27 दिसंबर को पिरोजपुर जिले के दम्रिताला गांव की बताई जा रही है। परिवार के सदस्यों के मुताबिक आग लगने के वक्त वे घर के अंदर फंसे हुए थे क्योंकि दरवाजे बाहर से बंद थे। कुल आठ लोग टिन और बांस की बाड़ काटकर बाहर निकलने में कामयाब रहे। लेकिन उनके घर, सामान और पालतू जानवर पूरी तरह जलकर राख हो गए।

स्थानीय पुलिस ने पांच संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के मुताबिक आग लगने की सटीक वजहों का पता नहीं चल पाया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हमलावरों ने एक कमरे में कपड़े भरकर आग लगा दी, जिससे आग तेजी से पूरे घर में फैल गई।

घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें लोग आग को बुझाने की कोशिश करते दिख रहे हैं।

6 महीने में अल्पसंख्यकों पर हमले की 71 घटनाएं

बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफईशनिंदा यानी धर्म का अपमान करने के आरोपों से जुड़े मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। जून से दिसंबर 2025 के बीच ऐसे कम से कम 71 मामले दर्ज किए गए हैं।

यह जानकारी बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर काम करने वाले संगठन 'ह्यूमन राइट्स कांग्रेस फॉर बांग्लादेश माइनॉरिटीज' की रिपोर्ट में सामने आई है।मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमले के लिए हर बार एक ही तरह का तरीका अपनाया जा रहा है।

पहले सोशल मीडिया पर आरोप, फिर तुरंत गिरफ्तारी, उसके बाद भीड़ का इकट्ठा होना और हिंदू इलाकों पर हमला। अब ईशनिंदा के आरोप डर फैलाने और अल्पसंख्यकों को दबाने का हथियार बनते जा रहे हैं।

बांग्लादेश में 18 दिसंबर को हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को भीड़ ने ईशनिंदा के झूठे आरोप में मार दिया था।

HRCBM का कहना है कि ये घटनाएं देश के 30 से ज्यादा जिलों में फैली हुई हैं। रंगपुर, चांदपुर, चटगांव, दिनाजपुर, खुलना, कुमिल्ला, गाजीपुर, टांगाइल और सिलहट जैसे कई इलाकों में ऐसे मामले सामने आए हैं।

उसका आदेश अगली सुनवाई तक लागू नहीं होगा

अरावली विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर लगाई रोक, सरकार से पूछे सवाल

नईदिल्ली (एजेंसी)। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली की समान परिभाषा को लेकर उपजे विवाद के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने 20 नंवबर को अरावली पर्वतमाला की परिभाषा को लेकर दिए अपने ही आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कह उसका आदेश अगली सुनवाई तक लागू नहीं होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी, 2026 के लिए निर्धारित भी कर दी।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की अवकाश पीठ ने कहा, समिति की रिपोर्ट और पिछले महीने कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों को गलत तरीके से समझा जा रहा है और कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। कोर्ट ने कहा, इस अदालत की किसी रिपोर्ट या निर्देश को लागू करने से पहले, निष्पक्ष, तटस्थ और स्वतंत्र विशेषज्ञ की राय पर विचार किया जाना चाहिए। यह कदम निश्चित मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आवश्यक है।

कोर्ट ने केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा कि क्या व्यापक रूप से प्रचारित आलोचना, जिसमें कहा गया है कि नई परिभाषा के तहत 11,000 से अधिक पहाड़ियां खनन के मानदंडों को पूरा करेंगी, वैज्ञानिक रूप से सटीक है, और क्या ऐसे निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए व्यापक वैज्ञानिक मानचित्रण की आवश्यकता है? कोर्ट ने कहा कि नई परिभाषा में मौजूद महत्वपूर्ण अस्पष्टताओं को दूर करना होगा। उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

कोर्ट ने सरकार से उसके 20 नवंबर को जारी किए गए आदेश को लागू करने से पहले 5 अहम सवालों को स्पष्ट करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा, क्या अरावली पर्वतमाला की परिभाषा को 500 मीटर के क्षेत्र तक सीमित करने से संरक्षण क्षेत्र को छोटा कर एक संरचनात्मक विरोधाभास उत्पन्न होता है? क्या इस परिभाषा ने गैर-अरावली क्षेत्रों के दायरे को व्यापक बना दिया है जहां विनियमित खनन की अनुमति दी जा सकती है?

कोर्ट ने सरकार से पूछा, क्या अंतरालों में विनियमित खनन की अनुमति दी जानी चाहिए - विशेष रूप से जहां 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले दो पहाड़ी क्षेत्र लगभग 700 मीटर की दूरी से अलग हों? कोर्ट ने आगे पूछा, अरावली पर्वतमाला की पारिस्थितिक निरंतरता को कैसे संरक्षित किया जा सकता है? यदि कोई महत्वपूर्ण विनियामक खामी पाई जाती है, तो क्या सीमा की संरचनात्मक अखंडता को बनाए रखने के लिए व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होगी?

प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य सचिवों की बैठक में भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर दिया जोर

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राजधानी नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की पांचवीं बैठक की। इस कार्यक्रम का मकसद केंद्र और राज्यों को देश की राष्ट्रीय ग्रोथ के लिए अपनी प्राथमिकताओं को एक साथ लाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म %एक्स% पर सम्मेलन की तस्वीरें साझा कीं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने मुख्य सचिवों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस वर्ष का विषय था %विकसित भारत के लिए मानव पूंजी%। उन्होंने कहा, मैंने इस बात पर अपने विचार साझा किए कि हम सब मिलकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने, गरीबों को सशक्त बनाने और विकसित भारत के अपने सपने को साकार करने के लिए कैसे काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों से विनिर्माण को प्रोत्साहित करने, व्यापार करने में सुगमता बढ़ाने और सेवा क्षेत्र को मजबूत करने का आह्वान किया गया। आइए, भारत को वैश्विक सेवा क्षेत्र का महाशक्ति बनाने का लक्ष्य रखें।

लोग सियासी लाभ लेने की कोशिश कर रहे', हाईकोर्ट जजों पर आरोप लगाए जाने पर शीर्ष कोर्ट की टिप्पणी

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि कुछ लोग उन्नाव दुष्कर्म मामले का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। शीर्ष कोर्ट ने यह टिप्पणी तब की, जब निष्कासित भाजपा नेता कुलदीप सेंगर के वकीलों ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के उन जजों के खिलाफआरोप लगाए जा रहे हैं, जिन्होंने सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित किया था।

हाईकोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को यह कहते हुए निलंबित कर दिया था कि वह पहले ही सात साल और पांच महीने जेल में बिता चुका है। तीन जजों की अवकाशकालीन पीठ की अध्यक्षता कर रहे मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, 'हम जानते हैं। हम कोई संकीर्ण सोच वाले लोग नहीं हैं। हम जानते हैं कि लोग राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग ही ऐसा कर रहे हैं।'

सेंगर की ओर से वरिष्ठ वकील एन. हरिहरन पेश हुए। उन्होंने शीर्ष कोर्ट को बताया कि इस मामले की सुनवाई करने वाले हाईकोर्ट के जजों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को जजों के खिलाफबयान या आरोप लगाने से बचना चाहिए। हरिहरन ने कहा, वे यह सब राष्ट्रीय टेलीविजन चैनलों पर कर रहे हैं। सेंगर की ओर से पेश एक अन्य वकील ने बताया कि हाईकोर्ट के जजों की तस्वीरें प्रसारित की जा रही हैं।

हरिहरन ने कहा कि जजों पर आरोप लगाने का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है और यह चिंता का विषय है। इसके बाद पीठ ने टिप्पणी की कि ऐसे लोग यह बात भूल जाते हैं कि सेंगर को न्यायपालिका ने ही दोषी ठहराया था। अवकाशकालीन पीठ में न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह भी शामिल थे। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा, स्पष्ट रूप से कहें तो ये जज हमारे यहां सर्वश्रेष्ठ जजों में से हैं।

चार दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य समापन, बाबा साहेब अंबेडकर इलेवन बनी विजेता, युवाओं में दिखा जबरदस्त जोश

राजनांदगांव (समय दर्शन)। बसंतपुर प्रीमियम लीग का चार दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट उत्साह और रोमांच के साथ संपन्न हुआ। फाइनल मुकाबले में बाबा साहेब अंबेडकर इलेवन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चंद्रशेखर आजाद इलेवन को हराकर खिताब अपने नाम किया। पूरे टूर्नामेंट के दौरान मैदान पर खिलाड़ियों का जोश और दर्शकों की भारी भीड़ खेल प्रेम का प्रमाण बनी रही।

टूर्नामेंट के पहले दिन उद्घाटन अवसर पर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार और निगम नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने फीता काटकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और खिलाड़ियों को खेल भावना व अनुशासन के साथ खेलने की सीख दी। दूसरे दिन डॉ. बलदेव प्रसाद मिश्र स्कूल के प्राचार्य कैलाश शर्मा अतिथि के रूप में पहुंचे, जिनका आयोजन समिति ने स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। उन्होंने आयोजन समिति और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।

तीसरे दिन विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के पदाधिकारी नंदू राम साहू, अनूप श्रीवास, योगेश बागड़ी, त्रिगुण सदानी, शिव वर्मा और सोमेस शर्मा अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान जिला क्रिकेट संघ के सचिव योगेश बागड़ी का जन्मदिन भी मनाया गया। अतिथियों ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया और आयोजन समिति को भविष्य में भी ऐसे आयोजन करने के लिए प्रेरित किया।

समापन अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व सांसद अभिषेक सिंह सहित पार्षद शेखर यादव, राजेश यादव, मोहन सिन्हा, पूर्व पार्षद देवशरण सेन, मंडल अध्यक्ष गोलु गुप्ता, सुमित भाटिया, आर्किटेक्ट संघ अध्यक्ष नवीन साहू सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अतिथियों ने युवाओं को नशामुक्ति, खेल से जुड़े रहने और महापुरुषों के आदर्शों को अपनाने का संदेश दिया। सभी टीमों के नाम महापुरुषों के नाम पर रखे जाने की सराहना की गई। आईपीएल की तर्ज पर आयोजित इस टूर्नामेंट में 104 खिलाड़ियों की नीलामी कर 8 टीमें बनाई गईं। टीमों के नाम गुरु गोविंद सिंह इलेवन, वीर महाराणा प्रताप इलेवन, बाबा साहेब अंबेडकर इलेवन, छत्रपति शिवाजी महाराज इलेवन, डॉ. अब्दुल कलाम इलेवन, सुभाषचंद्र बोस इलेवन, भगत सिंह इलेवन और चंद्रशेखर आजाद इलेवन रखे गए।

फाइनल मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए चंद्रशेखर आजाद इलेवन ने 10 ओवर में 127 रन बनाए। जवाब में बाबा साहेब अंबेडकर इलेवन ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए आखिरी ओवर में लक्ष्य हासिल कर रोमांचक जीत दर्ज की।

समापन पर संरक्षक सुनील सेन ने सभी खिलाड़ियों, अतिथियों, निर्णायकों और दर्शकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से युवाओं को सकारात्मक दिशा मिलती है और क्षेत्र में खेल संस्कृति को मजबूती मिलती है।

ग्राम कौंदकेरा में 51 लाख और किरवई में 36 लाख 86 हजार रूपये की लागत से बनेगी पक्की सड़क

गरियाबंद (समय दर्शन)। राजिम विधानसभा क्षेत्र के फिंगेश्वर विकासखंड में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक सकारात्मक पहल के तहत दो महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण कार्य प्रगतिरत् है। क्षेत्र के बाहूल्य जनसंख्या वाले ग्राम कौंदकेरा में गनपत घर से चांगबाधा तक 550 मीटर लंबी सड़क का निर्माण 51.05 लाख रुपये की स्वीकृत लागत से किया जा रहा है ।जिसमें नाले के पार दो वार्ड का बसाहट है ।जिसमें लगभग 700 जनसंख्या निवासरत् है,जिसके दृष्टिगत बरसात के दौरान यह क्षेत्र टापू में परिवर्तित हो जाती है,आना-जाना पूर्णत: बाधित हो जाती है ।इस स्वीकृति के मिलने से लोग सुगमता से मुख्य सड़क से जुड़ पाएंगे एवं अन्य क्षेत्रीय विकास कार्य संभव हो पाएगी ।इसी प्रकार बेलटुकरी रोड से मां पुजेरिनदाई मंदिर, किरवई तक 500 मीटर लंबी सड़क का निर्माण 36.86 लाख रुपये की लागत से किया जा रहा है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात सड़क निर्माण कार्य हेतु लोकृति कंस्ट्रक्शन,दुर्ग के साथ अनुबंध किया गया है ।दोनों सड़कों का भूमिपूजन राजिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक रोहित साहू के करकमलों द्वारा जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ ।भूमिपूजन अवसर पर क्षेत्रवासियों में हर्ष एवं उत्साह का वातावरण देखने को मिला। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण को क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए शासन एवं जनप्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त किया। ग्राम कौंदकेरा के सरपंच राधिका यादव कहा कि सड़कों के निर्माण से आवागमन सुगम होगा,जिससे स्वच्छता,शिक्षा, स्वास्थ्य सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक आसानी से पहुंच सकेगा। यह परियोजना क्षेत्र के समग्र, सतत एवं संतुलित विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।

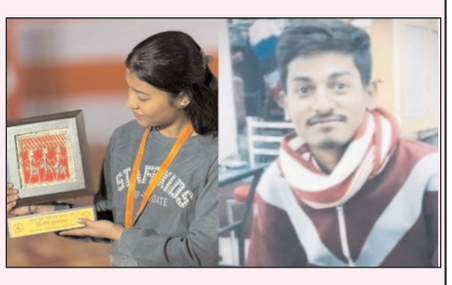

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जिला स्तरीय तीन दिवसीय कलम बंद-काम बंद आंदोलन से कार्यालयों में पसरा सन्नाटा

चार दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य समापन, बाबा साहेब अंबेडकर इलेवन बनी विजेता, युवाओं में दिखा जबरदस्त जोश

समर्थन एवं सहभागिता हेतु संगठनात्मक अपील मोदी की गारंटी लागू करने की मांग

सारंगढ़ बिलाईगढ़ (समय दर्शन)। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा डीए, वेतन विसंगति, कैशलेस उपचार सुविधा सहित 11 सूत्रीय लंबित मांगों के समाधान हेतु मोदी की गारंटी लागू करो अभियान के अंतर्गत तृतीय चरण जिला स्तरीय कलम बंद, काम बंद आंदोलन आयोजित किया जा रहा है ।शासन द्वारा कर्मचारियों से किए गए वादों की अनदेखी के विरोध में यह संघर्ष अब निर्णायक चरण में पहुँच चुका है। सभी कर्मचारी, अधिकारी एकजुट होकर अपने अधिकारों व सम्मान हेतु संघर्षरत हैं ।फेडरेशन की प्रमुखा 11 सूत्रीय मांगें इस प्रकार है:-

केंद्र सरकार के समान कर्मचारियों एवं पेंशनरों को देय तिथि से महंगाई भत्ता (ष्ठ) लागू किया जाए।

डीए एरियर्स की राशि कर्मचारियों के तक्क्न खाते में समायोजित की जाए। सभी कर्मचारियों को चार स्तरीय समयमान वेतनमान दिया जाए।

लिपिकों, शिक्षकों, स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग सहित विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगतियों को दूर करने पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए।

प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए संपूर्ण सेवा लाभ दिया जाए। पंचायत सचिवों का शासकीयकरण किया जाए।

सहायक शिक्षकों एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों को तृतीय समयमान वेतनमान दिया जाए। नगरीय निकाय के कर्मचारियों को नियमित। मासिक वेतन एवं समयबद्ध पदोन्नति दिया जाए।

अनुकंपा नियुक्ति नियमों में 10 प्रतिशत सीलिंग में शिथिलीकरण की जाए। प्रदेश में कैशलेश सुविधा लागू की जाए। अर्जित अवकाश नगदीकरण 300 दिवस की जाए।

नुक्कड़ नाटक, ि ज और योग से दिया नशामुक्ति का संदेश

राजनांदगांव (समय दर्शन)। कलेक्टर के मार्गदर्शन में समाज कल्याण विभाग एवं समता जन कल्याण समिति द्वारा संचालित नशामुक्ति केंद्र मोहला के तत्वावधान में नशामुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) के अंतर्गत 27 दिसंबर 2025 को ग्राम पंचायत काणे (मरकाटोला), विकासखंड मोहला में नशामुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान लोक सांस्कृतिक कलाकारों ने नशामुक्ति पर आधारित नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर नशे के दुष्प्रभावों को प्रभावी ढंग से बताया। इसके बाद ग्रामीणों के साथ कौन बनेगा नशामुक्त व्यक्ति नामक क्विज गेम खेला गया, जिसमें ग्रामीणजनों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। नशामुक्ति से जुड़े सवालों के सही जवाब देने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में नागपुर की सुख शांति समाधान योग संस्था से आए प्रसिद्ध योग गुरु सचिन माथुरकर ने योग के माध्यम से नशे से दूर रहने का संदेश दिया और उपस्थित ग्रामीणों को नशामुक्त रहने की शपथ दिलाई।

नशामुक्ति केंद्र के संचालक ने ग्रामीणों को जानकारी देते हुए बताया कि मोहला में संचालित नशामुक्ति केंद्र में नशे से पीड़ित व्यक्तियों को भर्ती कर नि:शुल्क भोजन, आवास, परामर्श एवं दवाइयों की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीणजन मौजूद रहे और सभी ने नशामुक्त समाज के निर्माण में सहयोग करने का संकल्प लिया।

अनुसूचित जाति वर्ग के लिए पीएम-अजय योजना के तहत स्वरोजगार हेतु आवेदन 12 जनवरी 2026 तक आमंत्रित

दुर्ग (समय दर्शन)। जिले में अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र हितग्राहियों को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु अनुसूचित जाति वर्ग हेतु अभ्युदय (पीएम-अजय) योजना के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना के तहत जो हितग्राही अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें बैंकों के माध्यम से न्यूनतम 1 लाख के ऋण की स्वीकृति पर 50 हजार या ऋण राशि का 50 प्रतिशत (जो भी कम हो) अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा।

जिला अंत्यावसायी सहकारी समिति मर्यादित दुर्ग से प्राप्त जानकारी अनुसार इस योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के व्यवसायों जैसे किराना, मनिहारी, कपड़ा दुकान, नाई सेलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, फैन्सी स्टोर, मोटर मैकेनिक, सायकिल मरम्मत, टीवी-रेडियो-मोबाइल रिपेयरिंग, वाइंडिंग, मुर्गीपालन, बकरी पालन, सब्जी व्यवसाय, दोनापत्तल निर्माण, लघु एवं फुटकर उद्योग सहित स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य व्यवसायों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

भाजपा सरकार लगातार मजदूर,किसान और गरीब विरोधी नीतियां थोप रही-कांग्रेस

बसना (समय दर्शन)। जिला कांग्रेस कमेटी एवम फुलझर स्टेट के राजा पूर्व मंत्री राजा श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह जी के निर्देश पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 140 वें स्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना का नाम बदले जाने के फैसले के खिलाफकांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाते हुए एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने इसे भाजपा सरकार की जनविरोधी और तानाशाही सोच का परिचायक बताते हुए कहा कि गरीबों के हक पर डाका डालने का यह सीधा प्रयास है। धरने में वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंडी अध्यक्ष मंजीत सिंह सलूजा ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की जनकल्याणकारी योजनाओं के नाम मिटाकर भाजपा अपनी विफलताओं को छिपाना चाहती है, लेकिन जनता सब समझती है ।पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष तौक़ीर सरवर दानी ने कांग्रेस स्थापना दिवस पर कांग्रेस के स्वर्णिम इतिहास पट प्रकाश डाले आजादी से मनरेगा कानून भोजन का अधिकार और भी देश के लिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा किये गए कार्यो की जानकारी दी एवम केंद्र और राज्य सरकार के जनविरोधी नीतियों का पुरजोर रूप से विरोध किया ।कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार लगातार मजदूर, किसान और गरीब विरोधी नीतियां थोप रही है और ऐतिहासिक योजनाओं के नाम बदलकर अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया कि वह भाजपा की जनविरोधी नीतियों के खिलाफसड़क से सदन तक संघर्ष जारी रहेगा ।इस कार्यक्रम मैं मुख्य रूप से ,जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी इस्तियाक खैरानी ब्लॉक अध्यक्ष विजय साहू, नरेंद्र साव, रबी कश्यप, गुरु बख्श सिंह आहुजा, राधेश्याम, रज्जू छाबड़ा, केशव, महिपाल सिंह जटाल, खालिद दानी, शिवनायक, खिरोध नाग, दक्ष्य प्रधान, यासमिन बेगम, नसरीन बानो, लक्ष्मी दास, योगेश साव, किर्तन साहू, तौसिफ इमाम सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन मौजूद रहे।

अवैध धान परिवहन और भंडारण पर प्रशासन की कार्रवाई, 1100 कट्टा धान जप्त

महासमुंद(समय दर्शन)। जिले में अवैध धान खरीदी, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। महासमुन्द कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर गठित संयुक्त टीम लगातार क्षेत्र में निरीक्षण कर रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है।

इसी तारतम्य में बागबाहरा विकासखंड में एसडीएम श्रीमती नमिता मारकोले के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने दो अलग-अलग मामलों में कुल 1100 कट्टा धान जब्त किया।

वाहन से 300 कट्टा धान जब्त

निरीक्षण के दौरान ग्राम टेमरी में एक वाहन को अवैध रूप से धान परिवहन करते हुए रोका गया। जांच में वाहन से 300 कट्टा धान बरामद हुआ, लेकिन चालक द्वारा धान से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका। राजस्व, खाद्य और मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए धान को जब्त कर मंडी समिति के सुपुर्द किया। दूसरी कार्रवाई में सिद्ध ट्रेडर्स, कोमाखान के प्रोपराइटर आशीष जैन के ग्राम मौलीमुड़ा नवाडीह स्थित गोदाम का निरीक्षण किया गया। यहां 800 कट्टा धान अवैध रूप से भंडारित पाया गया। संबंधित पक्ष द्वारा संतोषजनक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने पर मंडी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया और धान को जब्त कर मंडी समिति को सौंप दिया गया। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध धान खरीदी, परिवहन एवं भंडारण के खिलाफयह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि किसानों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।

किसानों को धान बिक्री करने में आ रही गंभीर समस्याओं को लेकर जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा गया

जांजगीर (समय दर्शन)। जिस किसान का कुल 5 एकड़ कृषि भूमि है उसको लापरवाह स्थानीय अमलों द्वारा पूरा का पूरा अन्य फसल के नाम भौतिक सत्यापन कर दिया गया है जो बहुत ही गंभीर विषय है।

त्वरित समाधान नहीं होने पर किसानों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी

गबेल समाज के प्रदेश अध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता लालू गबेल के नेतृत्व में मालखरौदा विकास खंड क्षेत्र के पीड़ित किसानों ने आज 29 दिसम्बर 2025 को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मालखरौदा के समक्ष अपनी पीड़ा रखी और त्वरित निदान हेतु कलेक्टर ने नाम ज्ञापन सौंपे। जिस पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मालखरौदा द्वारा शीघ्र कार्रवाई कर समस्या का निदान कराने आश्वासन दिया।

ज्ञापन में किसानों ने बताया कि किसी किसी किसान का पूरा का पूरा रकबा को ही अन्य फसल के नाम भौतिक सत्यापन कर दिया गया है, वही बहुत से छोटे किसानों का अधूरा रकबा धान खरीदी पोर्टल में दर्ज किया गया है।

किसान हित में शासन की इस महत्वपूर्ण कार्य में स्थानीय प्रशासन द्वारा बड़ी घोर लापरवाही बरती गई है जिससे किसान मानसिक शारीरिक रूप से काफी परेशान है। किसान अपनी समस्याओं को पूर्व से ही लगातार स्थानीय प्रशासन को लिखित सूचना आवेदन देते आ रहे है उसके वाबजूद लापरवाह अधिकारियों द्वारा कोई सुध नहीं लिया जा रहा बल्कि उल्टा किसानों से बुरा व्यवहार किया जाता है उनके पास किसानों की बात सुनने तक का समय नहीं रहता और अपनी समस्या सरकार के पास लेके जाओ कहा जाता है। अधिकारियों द्वारा किसानों के अति गंभीर समस्या को फर्जी कार्य कहा जाता है। किसानों ने यह भी बताया कि जो बड़े किसान है और धान खरीदी लिमिट कम होने के कारण उनका तीन बार टोकन में भी पूरा धान बिक्री नहीं हो पा रहा तो वहीं धान खरीदी केंद्रों में मापदंड से अधिक मनमानी धान तौल कर लिया जा रहा जो किसानों के साथ सरासर अन्याय है।

गिरदावरी और भौतिक सत्यापन में संबंधित स्थानीय प्रशासन ने जिस तरह से घोर लापरवाही की है यह वास्तव में शासन को बदनाम कर रही है जो छत्तीसगढ़ सरकार के लिए गंभीर चिंतन का विषय है।

पीड़ित किसानों ने शासन प्रशासन से त्वरित निदान की मांग रखी है अन्यथा किसान उग्र आंदोलन पर उतारू होंगे जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।

पीड़ित किसानों में मुख्य रूप से भरत राकेश गबेल मुक्ता, राधेश्याम चंद्रा मोहतरा, कुश कुमार वर्मा सारसकेला, लव कुमार गबेल सारसकेला, उमाशंकर चंद्रा पिहरीद, अरुण प्रकाश वर्मा सारसकेला, जीवन गबेल सुलौनी, प्रकाश गबेल जोरवा,ललित चंद्रा मालखरौदा, दादू चंद्रा सिंघरा, गेंद लाल गवेल जोरवा, संतोष ननकी दाऊ गबेल मुक्ता, धनंजय वर्मा सारसकेला, तुलेश्वर साहू सिंघरा, रेशम लाल चंद्र सिंघरा, पुरुषोत्तम चंद्रा सिंघरा, नारायण चंद्रा सिंघरा, लक्ष्मी प्रसाद चंद्रा चिखली, उमेन्द सिंह सिदार भुतहा, विजय कुमार जोरवा, अजीत पटेल मुक्ता, मिथलेश चंद्रा पिहरीद, तरुण गबेल परसी व अन्य किसान शामिल है।

इस अवसर किसानों को कमलेश गबेल ढीमानी, अधिवक्ता मनोज गबेल, मीडिया प्रभारी हरि गवेल पोता द्वारा विशेष सहयोग प्रदान किया गया।

संक्षिप्त-खबर

आम नागरिक से लेकर सरकारी कर्मचारी तक विष्णु से नाराज़

बिलासपुर (समय दर्शन)। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार के खिलाफ इस समय दो तरफ प्रहार हुआ । एक और विभिन्न सरकारी कर्मचारी यूनियन और अधिकारी 11 सूत्री मांगों को लेकर तीन दिवसीय हड़ताल पर हैं दूसरी और अलग-अलग शहरों में आम नागरिक जिम ग्रामीण भी शामिल हैं सरकार के खिलाफ धरने में बैठ गए। मुद्दा कहीं जनसुनवाई निरस्त करने (तमनार) तो कहीं घर उजाड़ कर सरकारी व्यवसायिक इमारत (लिंगियाडीह बिलासपुर) पर बैठे हैं। सरकारी कर्मचारी तो पहले भी अलग-अलग विभाग राजस्व, एनएचएम, शिक्षा, मंडी, सहकारिता हड़ताल पर जा चुके हैं। इस बार पूरे कर्मचारी एक साथ हड़ताल पर चले गए।

चुनाव पूर्व भाजपा द्वारा दी गई मोदी की गारंटी अब कर्मचारी ही मुख्यमंत्री को याद दिला रहे हैं और बता रहे हैं कि संकल्प पत्र में किस तरह 100 दिन के भीतर सब पूरा हो जाना था। 29 तारीख से जब कर्मचारी अधिकारी की हड़ताल शुरू होने वाली थी तो उपमुख्यमंत्री शासन के 2 साल पूरे होने पर प्रेस वार्ता कर रहे थे। बता रहे थे सरकार की उपलब्धियां पर वास्तविकता यही है कि जंगल से लेकर नया रायपुर तक अर्थात चरण से लेकर सीखा तक विरोध दिखाई दे रहा है।

राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में राजनांदगांव के प्रतिभागियों ने किया शानदार प्रदर्शन

राजनांदगांव (समय दर्शन)। बिलासपुर में 23 से 25 दिसंबर तक आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2025 में राजनांदगांव जिले के प्रतिभागियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन किया। विभिन्न विधाओं में युवाओं की प्रतिभा ने निर्णायकों और दर्शकों को प्रभावित किया।

सहायक संचालक ए. एक्का ने जानकारी देते हुए बताया कि वाद-विवाद विधा में राजनांदगांव के नावेशचंद्र साहू ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं एकांकी नाटक विधा में प्रतिष्ठा सिंगाड़े ने द्वितीय स्थान हासिल किया। प्रस्तुत नाटक वो एक रात के लेखक एवं निर्देशक रितेश सिंगाड़े रहे, जो राजनांदगांव थिएटर ग्रुप की प्रस्तुति थी। दोनों प्रतिभागियों का चयन राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में होने वाले प्रतियोगिता के लिए छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने हेतु किया गया है।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा लोकनृत्य, लोकगीत, पंथी, सुआ, राउत नाचा, एकांकी, चित्रकला, कहानी लेखन, कविता लेखन, वाद-विवाद, पारंपरिक वेशभूषा और नवाचार रॉक बैंड सहित अन्य विधाओं में भी जिले के कलाकारों ने सराहनीय प्रदर्शन किया।

सहायक संचालक ने कहा कि यह सफलता प्रतिभागियों की कड़ी मेहनत, मार्गदर्शक अधिकारियों और प्रशिक्षकों के सतत सहयोग तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग के समन्वित प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने सभी विजेताओं, प्रतिभागियों, मार्गदर्शक अधिकारियों और सहयोगी स्टाफको बधाई देते हुए विश्वास जताया कि राजनांदगांव के युवा भविष्य में भी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले को गौरवान्वित करते रहेंगे।

धान उपार्जन को लेकर भ्रामक तथ्यों का खाद्य विभाग द्वारा खंडन

बेमेतरा (समय दर्शन)। ललित विश्वकर्मा, प्रभारी महामंत्री, जिला कांग्रेस कमेटी बेमेतरा द्वारा राज्य शासन से धान उपार्जन हेतु टोकन लिमिट बढ़ाए जाने के संबंध में प्रस्तुत आवेदन क्रमांक/2160 दिनांक 26.12.2025 के माध्यम से धान उपार्जन व्यवस्था को लेकर कुछ तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। खाद्य विभाग द्वारा उक्त आवेदन में उल्लिखित तथ्यों को भ्रामक एवं तथ्यहीन बताते हुए उनका स्पष्ट खंडन किया गया है। संदर्भित आवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि टोकन लिमिट नहीं बढ़ाए जाने की स्थिति में जिले के किसान धान विक्रय से वंचित रह जाएंगे तथा धान खरीदी की अंतिम तिथि 15.01.2026 बताते हुए दिनांक 30.12.2025 को जिले के समस्त धान उपार्जन केंद्रों में तालाबंदी किए जाने की बात कही गई है। खाद्य विभाग के अनुसार यह दोनों ही तथ्य किसानों को भ्रमित करने वाले हैं तथा शासन की धान उपार्जन व्यवस्था पर अनावश्यक प्रश्नचिन्ह लगाने जैसे हैं।

खाद्य विभाग द्वारा बताया गया कि अन्य जिलों के समान ही जिला बेमेतरा में भी इस कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक/1628 दिनांक 19.12.2025 के माध्यम से टोकन लिमिट संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, जिसके अनुरूप जिले में टोकन लिमिट संशोधित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए दिनांक 27.12.2025 को पुन: अद्यतन टोकन लिमिट से अधिक लिमिट निर्धारित करने का प्रस्ताव भी शासन को प्रेषित किया गया है। अत: यह कहना कि टोकन लिमिट नहीं बढ़ाई गई है, तथ्यात्मक रूप से गलत है। खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य शासन द्वारा धान उपार्जन की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 नहीं बल्कि 31 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। इस संबंध में आवेदन में प्रस्तुत तथ्य पूर्णत: भ्रामक हैं। 30 दिसम्बर 2025, मंगलवार को जिले के सभी धान उपार्जन केंद्रों में तालाबंदी किए जाने का आह्वान अवैधानिक एवं अनुचित है।

कवर्धा विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र को मिली बड़ी सौगात

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने 5.74 करोड़ रूपए के सड़क निर्माण कार्यों का किया भूमिपूजन

रायपुर। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने आज कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के वनांचल और ग्रामीण क्षेत्र को बड़ी सौगात देते हुए 5 करोड़ 74 लाख 87 हजार रुपये की लागत से तीन महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्यों का विधिवत पूजा-अर्चना कर भूमिपूजन किया। इन सड़क निर्माण कार्यों से क्षेत्र के ग्रामीणों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलने के साथ-साथ विकास को भी नई गति मिलेगी। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सर्वप्रथम मेन रोड से ग्राम कटगो तक 3 करोड़ 35 लाख रूपए लागत की 6.81 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। इस सड़क के निर्माण से वनांचल क्षेत्र के ग्रामीणों को आवागमन में होने वाली कठिनाइयों से निजात मिलेगी और ग्रामीणों का मुख्य मार्ग से सीधा संपर्क स्थापित होगा।

इसके पश्चात उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने मेन रोड से खिरसाली तक 1 करोड़ 36 लाख 50 हजार रूपए लागत के 4 किमी लंबी सड़क निर्माण का भूमिपूजन किया। वहीं मेन रोड से लाटा तक 1 करोड़ 02 लाख 90 हजार रूपए लागत की 2.80 किमी लंबे सड़क निर्माण कार्य का भी विधिवत भूमिपूजन किया।

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने ग्रामीणों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ग्रामीण विकास को लेकर पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि ग्राम कटगो में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल 263 आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनका निर्माण कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि गांवों में अधोसंरचनात्मक विकास को निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने ग्रामीणों को यह भी जानकारी दी कि आगामी नववर्ष के अवसर पर 01 जनवरी को भोरमदेव कॉरिडोर का भव्य भूमिपूजन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि भोरमदेव कॉरिडोर के निर्माण से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और कवर्धा जिले को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सभी ग्रामवासियों को इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि यह कॉरिडोर क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ईश्वरी साहू, जिला पंचायत सदस्य श्री लोकचंद साहू, श्री राम किंकर वर्मा सहित जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे।

संक्षिप्त समाचार

राज्यपाल डेका से विवेकानंद केन्द्र के पदाधिकारियों ने की सौजन्य भेंट

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज यहाँ लोकभवन में विवेकानंद केन्द्र कन्याकुमाारी की उपाध्यक्ष पद्मश्री निवेदिता रघुनाथ भिडे एवं राज्य के अन्य पदाधिकारियों ने सौजन्य भेंट की। उन्होंने केन्द्र की गतिविधियों के संबंध में राज्यपाल को अवगत कराया और आवश्यक सहयोग के लिए अनुरोध किया। राज्यपाल श्री डेका ने रायपुर स्थित विवेकानंद केन्द्र में संचालित कौशल प्रशिक्षण केन्द्र के लिए 10 कम्प्यूटर प्रदान करने की स्वीकृति दी। इस अवसर पर राज्य संगठक सुश्री रचना जानी, सह प्रांत संगठक सुश्री ऋतुमणि दत्त, नगर संचालक, रायपुर श्री चेतन तारवानी, नगर प्रमुख, रायपुर श्री आशीष दुबे, संपर्क प्रमुख, रायपुर श्री सिद्धार्थ जैन भी उपस्थित थे।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 'प्रतिदिन राजधानी' के कैलेंडर का किया विमोचन

रायपुर। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज राजधानी रायपुर से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र 'प्रतिदिन राजधानी' के वर्ष 2026 के कैलेंडर का विमोचन किया। 'प्रतिदिन राजधानी' ने समाचार पत्र के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर वर्ष 2026 के कैलेंडर को नए रूप और कलेवर में प्रकाशित किया है। नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ संवाद परिसर में कैलेंडर के विमोचन के दौरान नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस., वरिष्ठ पत्रकार श्री नारायण भोई, श्री रमेश पाण्डेय, श्री प्रहलाद दमाहे, श्री हरीश तिवारी, श्री अमृत सिंह, श्री हरिमोहन तिवारी और 'प्रतिदिन राजधानी' के स्थानीय संपादक श्री जतिन नचरानी भी मौजूद थे।

'बिहान योजना से जुड़ी महिला समूह की सदस्य के परिवार को मिला प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का लाभ

रायपुर। ग्रामीण गरीब परिवारों, विशेषकर महिलाओं को स्वयं- सहायता समूहों के माध्यम से संगठित कर, उन्हें कौशल विकास, वित्तीय समावेशन और आजीविका के अवसर प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने का एक सरकारी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना और सामाजिक रूप से सशक्त करना एवं गरीबी उन्मूलन है। स्वयं- सहायता समूहों को बैंकों से ऋण दिलाने और कम ब्याज दर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान से जुड़ी महिला स्व-सहायता समूहों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सुकमा जिले में कलेक्टर के निर्देशन और जिला पंचायत के सीईओ के मार्गदर्शन में यह कार्य प्रभावी रूप से किया जा रहा है। जिले के अंतिम छोर पर स्थित विकासखंड कोंटा की राधा कृष्णा महिला स्व-सहायता समूह की सदस्य श्रीमती अर्पणा बोस ढोंद्रा, निवासी कोंटा का 17 अक्टूबर 2025 को आकस्मिक निधन हो गया। इस दुःखद घटना के बाद जिला प्रशासन के निर्देशानुसार त्वरित कार्रवाई की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के सहयोग से अर्पणा बोस के बैंक खाते से जुड़ी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत बीमा दावा तैयार किया गया। आवश्यक दस्तावेजों के साथ यह प्रकरण भारतीय स्टेट बैंक, शाखा कोंटा में विधिवत जमा किया गया।

बैंक द्वारा सभी औपचारिकताएं समय पर पूर्ण कर बीमा दावा उच्च कार्यालय भेजा गया। इसके परिणामस्वरूप 26 दिसम्बर 2025 को मृतक सदस्य के नामिनी टिंकू बोस (पुत्र) को 2 लाख रुपये की बीमा राशि स्वीकृत कर उनके खाते में जमा की गई। इस पूरी प्रक्रिया में बिहान परियोजना की पीआरपी, एफएलसीआरपी तथा भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों का सराहनीय सहयोग रहा। समय पर मिली इस सहायता से शोकाकुल परिवार को आर्थिक संबल प्राप्त हुआ।

उल्लेखनीय है कि शासकीय योजनाएं, विशेषकर बिहान और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, संकट के समय जरूरतमंद परिवारों के लिए मजबूत सहारा बन रही हैं। 18-50 आयु वर्ग के बैंक खाताधारकों को 2 लाख रूपए का जीवन कवर देती है, जिसमें किसी भी कारण से मृत्यु होने पर परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलती है।

किसान की आड़ में अवैध धान व्यापार करने वाले को प्रशासन ने रंगे हाथों पकड़ा

रायपुर। बस्तर जिले में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के दिशा निर्देशों के अनुसार निरंतर किसानों से धान का उपार्जन किया जा रहा है साथ ही अवैध धान के विक्रय पर भी प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है। जिसका असर आज देखने को मिला जहां कलेक्टर श्री हरिस एस के निर्देश पर अवैध धान परिवहन के खिलाफचल रहे अभियान के तहत बकावंड विकासखण्ड के अनुविभागीय दंडाधिकारी श्री मनीष वर्मा ने बड़ी कार्रवाई की। सोमवार को धान उपार्जन केंद्र करपावंड के औचक निरीक्षण के दौरान प्रशासन ने व्यापारी और किसान की मिलीभगत से चल रहे एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया, जिसमें किसान के टोकन पर व्यापारी का धान खपाने का प्रयास किया जा रहा था। मामले की जांच में यह खुलासा हुआ कि जिस टोकन पर धान बेचा जा रहा था, वह कृषक उपेन्द्र भारती पिता अर्जुन भारती के नाम पर था। जमीनी हकीकत यह थी कि कृषक उपेन्द्र भारती आजीविका के सिलसिले में हैदराबाद में निवासरत हैं और उनकी जमीन पर खेती उनके भाई लखीधर भारती द्वारा की जा रही थी। लखीधर ने अपनी उपज के लिए 182 क्विंटल का टोकन कटवाया था, लेकिन खेत में वास्तविक उत्पादन केवल 100 क्विंटल ही हुआ। टोकन में बचे 80 क्विंटल के अंतर का गलत फायदा उठाने के लिए व्यापारी राजेश गुप्ता ने साजिश रची। व्यापारी ने मंडी करपावंड से ही धान अपने दो वाहन क्रमांक सीजी 17 केवाय 7204 और सीजी 17 केजे 9389 में लोड करवाया और ड्राइवरों के हाथ में उपेन्द्र भारती के टोकन की फेटोकॉपी थमाकर उन्हें उपार्जन केंद्र भेज दिया। मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने जब कड़ाई से पूछताछ की, तो ड्राइवर और किसान के भाई ने पूरा सच स्वीकार कर लिया। उनकी स्वीकारोक्ति के बाद एसडीएम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अवैध धान से भरे दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और उन्हें आगामी कार्यवाही हेतु थाना करपावंड के सुपुर्द कर दिया गया है।

प्रदेश के किसान आधुनिक कृषि यंत्रों से हो रहे हैं समृद्ध : बीज निगम द्वारा किसानों को अनुदान पर उपलब्ध कराये जा रहे आधुनिक कृषि यंत्र

रायपुर। प्रदेश के किसान खेती-किसानी में आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग कर आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं। वहीं विकसित भारत विजन की परिकल्पना की ओर अग्रसर हो रहे हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा किसानों को अनुदान पर आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसका बड़ी संख्या में किसान लाभ ले रहे हैं। किसान सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर खेती किसानी के उन्नत एवं आधुनिक तौर तरीके अपना रहे हैं, जिससे किसानों को पारंपरागत किसानी से अधिक फायदा हो रहा है। शासकीय अनुदान पर आधुनिक एवं उन्नत कृषि यंत्र किसानों को

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य शासन द्वारा कृषि के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित हैं जिनसे किसान लगातार लाभान्वित हो रहे हैं, चाहे वो उन्नत बीज हो या अन्य विभागीय योजनाएं। इसी क्रम में बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा किसानों के हित में शासकीय अनुदान पर आधुनिक एवं उन्नत किस्म में विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों को किसानों को उपलब्ध कराया जाता है द्य खेती किसानी के विभिन्न चरणों जुताई, बुआई, रोपाई, फसल कटाई जैसे सभी चरणों के लिए अनुदान पर कृषि यंत्र किसान के द्वारा चयन आधार पर उपलब्ध कराया जाता है, इससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। बीज निगम द्वारा किसानों को शक्ति चलित कृषि यंत्र जैसे - रोटावेटर, स्व चलित रीपर, पैडी ट्रांसप्लांटर, लेज़र लैंड लेवलर, पावर वीडर, मल्चर, थ्रेशर, सीड ड्रिल, सहित अन्य आधुनिक कृषि यंत्र अनुदान पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन कृषि यंत्रों के उपयोग से किसानों को समय की बचत के साथ-साथ श्रम लागत में भी कमी हो रही है। किसानों का कहना है कि आधुनिक यंत्रों के प्रयोग से खेती का कार्य कम समय में और अधिक सटीक तरीके से हो पा रहा है, जिससे फसल की गुणवत्ता बेहतर हुई है। परिणाम स्वरूप बाजार में उन्हें उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त हो रहा है और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है। बता दें कि बीज निगम का उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। निगम द्वारा किसानों की आवश्यकताओं के अनुसार कृषि यंत्र अनुदान पर उपलब्ध कराने की योजना क्रियान्वित है। जिससे कृषि क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा मिल रहा है।

वर्ष 2025-26 में अभी तक 882 किसान को अनुदान पर कृषि यंत्रों से लाभान्वित हो चुके हैं।

बस्तर पंडुम का वर्ष 2026 में भी होगा भव्य एवं आकर्षक ढंग से आयोजन

रायपुर। बस्तर अंचल की समृद्ध लोकपरंपराओं, जनजातीय संस्कृति, कला और विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से 'बस्तर पंडुम' का आयोजन वर्ष 2026 में भी गत वर्ष की भांति भव्य और आकर्षक रूप में किया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में विगत दिवस मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में उच्चस्तरीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में आयोजन की विस्तृत तैयारियों की समीक्षा की गई तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बस्तर पंडुम 2026 का आयोजन 10 जनवरी 2026 से 5 फरवरी 2026 तक तीन चरणों में प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत 10 से 20 जनवरी तक जनपद स्तरीय कार्यक्रम, 24 से 30 जनवरी तक जिला स्तरीय कार्यक्रम तथा 1 से 5 फरवरी तक संभाग स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस वर्ष बस्तर पंडुम में विधाओं की संख्या 7 से बढ़ाकर 12 की जा रही है। जिन विधाओं में प्रदर्शन एवं प्रतियोगिताएं होंगी, उनमें बस्तर जनजातीय नृत्य, गीत, नाट्य, वाद्ययंत्र, वेशभूषा एवं आभूषण, पूजा-पद्धति, शिल्प, चित्रकला, जनजातीय पेय पदार्थ, पारंपरिक व्यंजन, आंचलिक साहित्य तथा वन-औषधि प्रमुख हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने तैयारियों के संबंध में विभागीय अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की और आयोजन को सुव्यवस्थित, गरिमामय तथा अधिक प्रभावी स्वरूप में संपन्न कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बस्तर पंडुम, बस्तर की असली आत्मा और सांस्कृतिक विरासत का सशक्त मंच है।

बैठक में यह बताया गया कि बस्तर पंडुम 2026 का लोगो, थीम गीत और आधिकारिक वेबसाइट का विमोचन माँ दंतेश्वरी के आशीर्वाद के साथ मंदिर प्रांगण में ही मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर वरिष्ठ मांझीङ्गचालकी, गायताङ्गपुजारी, आदिवासी समाज के प्रमुखजन तथा पद्म सम्मान से अलंकृत कलाकार उपस्थित रहेंगे। इस बार विशेष रूप से भारत के विभिन्न देशों में कार्यरत भारतीय राजदूतों को आमंत्रित किए जाने पर भी चर्चा हुई, ताकि उन्हें बस्तर की अद्वितीय सांस्कृतिक धरोहर, परंपराओं और जनजातीय जीवन से अवगत कराया जा सके। साथ ही बस्तर संभाग के निवासी उच्च पदस्थ अधिकारी, यूपीएससी एवं सीजीपीएससी में चयनित अधिकारी, चिकित्सक, अभियंता, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि तथा देश के विभिन्न राज्यों के जनजातीय नृत्य दलों को आमंत्रित करने का भी निर्णय लिया गया।

प्रतिभागियों के पंजीयन की व्यवस्था इस बार ऑनलाइन और ऑफ्लाइन दोनों माध्यमों से करने का प्रस्ताव है, जिससे अधिकाधिक कलाकारों और समूहों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। उल्लेखनीय है कि बस्तर अंचल की कला, शिल्प, त्योहार, खान-पान, बोली-भाषा, आभूषण, पारंपरिक वाद्ययंत्र, नृत्य-गीत, नाट्य, आंचलिक साहित्य, वन-औषधि और देवगुड़ियों के संरक्षण एवं प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत बस्तर संभाग के सात जिलों के 1,885 ग्राम पंचायतों, 32 जनपद पंचायतों, 8 नगरपालिकाओं, 12 नगर पंचायतों और 1 नगर निगम क्षेत्र में तीन चरणों में आयोजन होगा। इस आयोजन के लिए संस्कृति एवं राजभाषा विभाग को नोडल विभाग नामित किया गया है।

बैठक में उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल, संस्कृति सचिव श्री रोहित यादव, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, संचालक श्री विवेक आचार्य सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने लिया तैयारियों का जायजा, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश

भोरमदेव पर्यटन कॉरिडोर का 01 जनवरी को होगा भूमिपूजन

रायपुर। 01 जनवरी को छत्तीसगढ़ के पर्यटन विकास को नई दिशा देने वाले भोरमदेव पर्यटन कॉरिडोर का भूमिपूजन होने जा रहा है। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की पहल से लगभग 146 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाले इस परियोजना का भूमिपूजन केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के करकमलों से संपन्न होगा।

आयोजन की तैयारियों का जायजा लेने उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने आज भोरमदेव मंदिर परिसर स्थित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर तैयारियों की विस्तार से जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने मुख्य मंच एवं बैठक व्यवस्था, जनसमुदाय के बैठक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात, पार्किंग, पेयजल सहित आयोजन से संबंधित अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ईश्वरी साहू, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्रवंशी, सभापति डॉ वीरेंद्र साहू, कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा, एएसपी श्री पुष्पेंद्र सिंह बघेल, एडीएम श्री विनय पोयाम सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

भोरमदेव मंदिर परिसर अपनी प्राचीन स्थापत्य कला और धार्मिक आस्था के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटन कॉरिडोर के निर्माण से यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जिससे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी गति मिलेगी। भोरमदेव पर्यटन कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत सड़क, पार्किंग, व्यू प्वाइंट, पर्यटक सुविधा केंद्र, सौंदर्यीकरण एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इससे न केवल पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

राज्य सरकार का लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थलों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जाए। भोरमदेव कॉरिडोर इसी सोच का परिणाम है, जो आने वाले वर्षों में क्षेत्र की पहचान को और मजबूत करेगा। भोरमदेव पर्यटन कॉरिडोर का भूमिपूजन न केवल नए साल की शुरुआत को खास बनाएगा, बल्कि छत्तीसगढ़ के पर्यटन मानचित्र पर एक नई उपलब्धि के रूप में दर्ज होगा। यह परियोजना राज्य के ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

संपादकीय

बाजार के विस्तार की उम्मीदें पूरी नहीं हुई

जीएसटी कटौती से एफएमसीजी कंपनियों की बिक्री में अक्टूबर में हुई बढ़ोतरी नवंबर में गायब हो गई। बाजार का दीर्घकालिक रुझान भी जारी रहा है। एसयूवी की बिक्री खूब बढ़ी है, मगर छोटी कारों के मामले में मामूली बढ़ोतरी ही दर्ज हुई। धूम-धड़ाके से बचत उत्सव मनाने के बाद अब बारी उसकी कीमत चुकाने की है। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस को लाल किले से जीएसटी ढांचे में बदलाव का एलान किया था। नवरात्रि के साथ नई दरें लागू हुईं, तो यह धारणा बनाने की कोशिश हुई कि भारतीय बाजार में मांग एवं उपभोग की कमी से उपजी तमाम आर्थिक समस्याओं का अब हल निकल आएगा। यह समाधान कितना हुआ, यह अपने-आप में महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। मगर एक सवाल राजकोष पर इसके असर का भी है, जिसकी ओर तब अनेक हलकों से ध्यान दिलाया गया था। अब मुद्दा सामने है। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजित पवार ने कहा है कि कल्याण योजनाओं पर अधिक खर्च के कारण पहले से ही राजकोषीय दबाव में चल रही राज्य सरकार को जीएसटी दरों में कटौती से सालाना 15 हजार करोड़ रुपये का नुकसान होने जा रहा है। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार उत्पाद शुल्कों में बदलाव पर विचार कर रही है। यानी जीएसटी में मिली राहत को उत्पाद शुल्क में वृद्धि से वापस लिया जाएगा। या फिर पहले से ही 9.32 लाख करोड़ रुपये के कर्ज बोझ तले दबी राज्य सरकार नए ऋण लेगी। कर्ज का गणित यह है कि उसका ब्याज चुकाना होता है और वह भी करदाताओं की जेब से ही आता है। कर्जदाता मोटी जेब वाली कंपनियां और लोग होते हैं, जबकि ज्यादा बोझ फटी जेब वालों पर पड़ता है। अब अगर जीएसटी कटौती से हुए फायदों पर ध्यान दें, तो कुछ ताजा आंकड़े इसकी कहानी बता देते हैं। रोजमर्रा की जरूरत के सामान बनाने वाली (एफएमसीजी) कंपनियों की बिक्री दर में अक्टूबर में हुई बढ़ोतरी नवंबर में गायब हो गई। और अक्टूबर की कथा भी यह थी कि बिक्री में बढ़ोतरी बाजार के दीर्घकालिक रुझान के अनुरूप ही रही। मसलन, अक्टूबर- नवंबर के साझा आंकड़ों के मुताबिक कार बाजार में एसयूवी की बिक्री 17 फीसदी बढ़ी, लेकिन छोटी कारों के मामले में यह तीन प्रतिशत ही रही। यानी बाजार के विस्तार की उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं। लाभ धनी लोगों तक सीमित रहा, जबकि अब कीमत चुकाने का ज्यादा बोझ आम लोग उठाएंगे!

खुद बच्चों को प्रकृति के पर्यावरण में जीना सीखना होगा

संदीप जोशी

लखनऊ में जो हुआ उसको दिल्ली सरकार के धुंआसे व कुहासे से समझते हैं। दो महीने से दिल्ली में वायु गुणवत्ता के लगातार गिरने, और सूचकांक के तेजी से बढ़ने की खबरें आ रही थीं। ऐसे में सरकार के कुछ न कर पाने का खामियाजा दिल्ली के स्कूल और उसमें पढ़ने वाले बच्चों को भुगतना पड़ा। बच्चों पर स्कूल की सीमेंट दीवारों से निकल कर पेड़-पौधों के खुले वातावरण में खेलने पर पाबंदी लग गयी। लखनऊ के एकाना स्टेडियम पर होने वाला भारत और दक्षिण अफ्रीका का बीसमबीस मैच धुआंसे, जहरीली हवा व अपर्याप्त रौशनी के कारण रद्द हुआ। मैदान पर पहुंचे हजारों क्रिकेट प्रेमी दर्शक और अनेक खिलाड़ी व खेल प्रशासक प्रदूषण का खेल देखते रहे। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली के बाद अब उत्तर भारत के ज्यादातर शहर आ गए हैं। जरूरत की प्रकृति को नजरअंदाज कर स्वार्थ के लालच को महत्व देने से ही यह हालात बने हैं। कारण सिर्फ शहरों के ही विकास के लिए बनाई जा रही सत्ता की नीतियां रही हैं। पर्यावरण को दूषित न करने की जिम्मेदारी अगर समाज पर होती है तो सत्ता पर प्रदूषण न फैलाने देने का उत्तरदायित्व भी रहता है। क्या हम पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा पाए हैं? और क्या सत्ता अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहती है? फैलते एक्यूआई राक्षस को हमें एआई के तंत्र, और विवेक की सुधबुध से संवारना होगा। समाज की जेन-ज़ी पीढ़ी पर ही जंग लगी पीढ़ी के धतकर्मों को समझ कर संवारने की जिम्मेदारी है। स्वयं के चार-पहियाई सपनों में समाज के पैदल चलने व सार्वजनिक यातायात की सभ्यता को हरी-भरी संस्कृति से सहेजना होगा। लगातार घटते जंगल और कटते पेड़ों को सत्ता के स्वयंसेवी विकास से बचाना होगा। सत्ता-वैभव के दिल्ली व्यवहार का विस्तार ही कानपुर से लखनऊ तक, भोपाल से इंदौर तक, लुधियाना से चंडीगढ़ तक, शिमला से कुल्लू तक और गुड़गांव से पंचकूला तक फैल रहा है। आज के समय में विकास करने के लिए सत्ता, और विकसित होने के लिए जनता दोनों लालायित हैं। इकोसिस्टम या परिस्थिति के प्राकृतिक तंत्र को सत्ता के स्वार्थ तंत्र में बदला जा रहा हैं। बिना लोगों के व्यवहार को समझे, दिल्ली लखनऊ या इंदौर को सिंगापुर, लंदन व न्यूयॉर्क बनाने में लगे हैं। क्या ऐसे सपने देखना या दिखाना संभव है? लखनऊ में जो हुआ उसको दिल्ली सरकार के धुंआसे व कुहासे से समझते हैं। दो महीने से दिल्ली में वायु गुणवत्ता के लगातार गिरने, और सूचकांक के तेजी से बढ़ने की खबरें आ रही थीं। ऐसे में सरकार के कुछ न कर पाने का खामियाजा दिल्ली के स्कूल और उसमें पढ़ने वाले बच्चों को भुगतना पड़ा। बच्चों पर स्कूल की सीमेंट दीवारों से निकल कर पेड़-पौधों के खुले वातावरण में खेलने पर पाबंदी लग गयी। मजेदार ठंड की सुहानी धूप हो, और बच्चों को खुले में खेलने न दिया जाए तो शारीरिक व मानसिक विकास कैसे हो सकता है? और ऐसा पिछले दो-दशक से हर साल ठंड के मौसम में होता आ रहा है। माता-पिता की बेसमझ चिंता और न्यायालय के दबाव से घबराए स्कूल, अपनी समझ व विवेक खो बैठ। चार-पहिया व अन्य गाड़ियां से धुआंसा अपने धंधे में लगे लोग करते हैं जो अपने ही बच्चों के सर्वगुण विकास की अनदेखी करते हैं। सब मानते हैं आज के बच्चे ही कल का भविष्य होने वाले हैं। माता-पिता अपने द्वारा ही फैलाए प्रदूषण में अपने ही बच्चों को खेलने नहीं देना चाहते। न्यायालय जा कर स्कूलों को नियम-कायदे सिखाते हैं। न्यायालय स्कूलों पर दबाव डालता है। और धंधे में लगे स्कूल घबराकर अपना विवेक खोते हैं।

बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न पर आखिर खामोश क्यों हैं दुनिया के लोग?

कमलेश पांडे

भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में हिंदुओं पर उत्पीड़न एक लंबे अरसे से चली आ रही समस्या है, जबकि उसके उदय में भारत सरकार की परोक्ष भूमिका रही है। कभी पूर्वी पाकिस्तान कहे जाने वाले बंगलादेश में अक्सर इस्लामिक कट्टरता ब्रेक के बाद मुखर हो जाती है, जो राजनीतिक अस्थिरता के दौरान अमूमन तेज हो जाती है। यह भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है और दुनियाभर में अल्पसंख्यक समूह के उत्पीड़न पर संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता का द्योतक है। हाल के दिनों में भारत और बंगलादेश के कूटनीतिक सम्बन्धों पर भी इन बातों का साफ असर महसूस किया जा सकता है।

यदि पुरानी बातें छोड़ भी दीं जाएं तो गत वर्ष यानी 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से बंगलादेश में हिंदू विरोधी हिंसा में पुन: उछाल आया है, जिसमें मंदिरों पर हमले, घरों में लूटपाट और हत्याएं शामिल हैं। इस पर भारत सरकार और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की महज खानापूर्ति वाली प्रतिक्रिया से वहां हिंदुओं पर संकट गहराता जा रहा है। इससे भारत में भी बंगलादेश विरोधी उत्तेजना स्वाभाविक है।

यदि हालिया घटनाओं पर नजर दौड़ाएं तो पता चलता है कि नवंबर 2024 से जनवरी 2025 तक 76 हमले दर्ज हुए, जबकि अगस्त 2024 से अब तक 23 हिंदुओं की हत्या और 152 मंदिरों पर आक्रमण की खबरें हैं। वहीं, 2025 में राजबाड़ी जिले में अमृत मंडल और दीपू चंद्र दास जैसे हिंदू युवकों की पीट-पीटकर हत्या हुई, साथ ही घरों में आगजनी के मामले सामने आए। इसकी एक बड़ी वजह बंगलादेश में हिंदुओं की जनसंख्या में निरंतर कमी होना भी है। आंकड़े बताते हैं कि 1971 में हिंदू बांग्लादेश की आबादी का 22त्न थे, जो अब घटकर 8त्न से कम रह गए हैं, जो मुख्यत: उत्पीड़न और पलायन के कारण हुआ है। एक अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च के मुताबिक, 16 लाख हिंदू भारत चले गए, क्योंकि बंगलादेश में हिंदुओं की भूमि हड़पना, बलात्कार और मंदिर तोड़फोड़ आम अपराध हैं। इससे जुड़े आंकड़े और रिपोर्ट की मानें तो 2025 के पहले छह महीनों में 258 हिंसा की घटनाएं हुईं, जिनमें 20 बलात्कार और 59 पूजा स्थलों पर हमले शामिल हैं। कुल 4 अगस्त 2024 से जून 2025 तक 2,244 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। जबकि अंतरिम सरकार पर निष्क्रियता का आरोप है, जिससे अपराधी बेखौफ हैं।

दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि बंगलादेश की कार्यवाहक सरकार के मुखिया मोहम्मद युनुस ने बांग्लादेश में हिंदू हत्याओं पर प्रत्यक्ष रूप से कोई स्पष्ट सार्वजनिक बयान या ठोस कार्रवाई नहीं की है, जिससे उनकी सरकार पर निष्क्रियता के आरोप लगे हैं। कई रिपोर्ट्स में हिंसा को उनकी कथित कट्टरपंथी नीतियों से जोड़ा गया है, लेकिन आधिकारिक प्रतिक्रिया में केवल सामान्य शांति अपील तक सीमित रहने का उल्लेख है। इसलिए उनपर आरोप लगते हैं और आलोचना भी होती है कि युनुस सरकार पर जमात-ए-इस्लामी जैसे कट्टरपंथी समूहों को संरक्षण दे रहे हैं, जिसके बाद हिंदू हत्याओं में वृद्धि हुई।

वहीं, भारतीय मीडिया और विपक्षी नेता भी उन्हें हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि युनुस ने भारत के दबाव में जांच के वादे किए बिना कोई स्पष्ट स्टैंड नहीं लिया। जहां तक अंतरराष्ट्रीय दबाव की बात है तो भारत और ब्रिटेन जैसे देशों ने युनुस से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया में कोई ठोस कदम नहीं दिखा। वहीं, बंगलादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने निर्वासन से युनुस पर हिंदू उत्पीड़न को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। जहां तक इस मसले पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया का सवाल है तो भारत सरकार ने लोकसभा में मामले उठाया, जबकि विश्व हिंदू परिषद ने विरोध प्रदर्शन किए। वहीं, ब्रिटिश सांसदों ने युनुस सरकार पर कार्रवाई की मांग की।

बता दें कि भारत विदेशों में हिंदुओं पर हो रहे उत्पीड़न को मुख्य रूप से कूटनीतिक दबाव, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आवाज उठाने और संबंधित देशों से न्याय की मांग करके रोकने का प्रयास करता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में हालिया घटनाओं पर विदेश मंत्रालय ने सख्त बयान जारी किए हैं, जहां दोषियों को सजा देने और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है।

जहां तक कूटनीतिक प्रयास की बात है तो भारतीय विदेश मंत्रालय बांग्लादेश में हिंदू युवकों की हत्या और घरों पर हमलों की कड़ी निंदा करता है तथा अंतरिम सरकार से कार्रवाई की अपेक्षा रखता है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ढाका में बांग्लादेशी समकक्ष से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चर्चा की। वहीं भारत उचित अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की दुर्दशा उजागर करता है, लेकिन सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी संबंधित देश की सरकार मानता है। जहां तक गृह मंत्रालय की भूमिका की बात है तो गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेश सीमा पर विशेष समिति गठित की है जो हिंदू अल्पसंख्यकों की स्थिति की निगरानी करती है और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। नागरिकता संशोधन कानून के जरिए उत्पीड़ित हिंदू, सिख आदि को भारत में शरण प्रदान की जा रही है।

वहीं, विभिन्न राष्ट्रवादी संगठनों ने भी इस मामले में पहल की है। खासकर आरएसएस ने अपनी शताब्दी बैठक में विदेशों में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए संकल्प पारित किया तथा संरक्षण तंत्र की मांग की। जबकि कुछ विश्लेषकों ने 'राइट टू प्रोटेक्ट' सिद्धांत अपनाने का सुझाव दिया है, जिसमें सीमा पर सुरक्षित क्षेत्र बनाने जैसे कदम शामिल हैं।हालांकि इस दिशा में चुनौतियां की काफी हैं, क्योंकि भारत विदेशी सरकारों पर दबाव बनाता है, लेकिन प्रत्यक्ष हस्तक्षेप सीमित रहता है क्योंकि संप्रभुता का सम्मान किया जाता है। वहीं वैश्विक शक्तियां जैसे अमेरिका-ब्रिटेन भी हिंसा की निंदा करती हैं, जो भारत के प्रयासों को मजबूती देती हैं। पिछले साल आपने देखा होगा कि चिन्मय कृष्ण दास, बांग्लादेश संमिलित सनातन जागरण जोत के प्रवक्ता और पूर्व इस्कॉन नेता, को 25 नवंबर 2024 को ढाका हवाई अड्डे से राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी का मुख्य कारण चटगांव में 25 अक्टूबर को हुई रैली में बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर केसरिया झंडा फहराने का आरोप था, जहां वे हिंदू अल्पसंख्यकों के आठ सूत्री मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी गिरफ्तारी शेख हसीना सरकार गिरने के बाद अल्पसंख्यक हिंसा के खिलाफ बड़े प्रदर्शनों (चटगांव और रंगपुर में) से जुड़ी थी, जिसे बांग्लादेशी अधिकारी राजद्रोह मानते हैं। बाद में चटगांव में वकील सैफुल इस्लाम की हत्या के मामले में भी उन्हें आरोपी दिखाया गया, जो उनकी गिरफ्तारी के बाद हुई हिंसक झड़पों से उपजा। अप्रैल 2025 में हाईकोर्ट ने राजद्रोह मामले में जमानत दी, लेकिन स्टे लग गया और वे जेल में हैं।

इसका तत्काल प्रभाव यह हुआ कि उनकी गिरफ्तारी के बाद पूरे बांग्लादेश में हिंदू समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किए, जिससे हिंसक झड़पें हुईं और एक व्यक्ति की मौत हो गई। स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसे समूहों ने इस्कॉन पर प्रतिबंध की मांग की। इस मुद्दे पर भारत और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया भी आई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने गिरफ्तारी और जमानत अस्वीकार पर गहरी चिंता जताई तथा बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। इससे भारत-बांग्लादेश संबंधों में तनाव बढ़ा, जहां भारत हिंदू अधिकारों पर जोर दे रहा है। इसका व्यापक प्रभाव पड़ा, क्योंकि यह घटना बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न का प्रतीक बनी, जिससे वैश्विक स्तर पर अल्पसंख्यक अधिकारों पर बहस तेज हुई। चिन्मय दास हिंदू समुदाय के प्रतिरोध के चिह्न बन गए। यद्यपि भारत-बंगलादेश एक दूसरे के पूरक हैं, फिर भी उसपर बढ़ता पाकिस्तानी प्रभाव भारत के लिए चिंता का सबब है। लिहाजा भारत सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह बंगलादेश के साथ कूटनीतिक स्तर पर कड़ाई बरते। अंतर्राष्ट्रीय कारोबारी स्तर पर प्रतिबंध लगाए। उसको शह देने वाले पाकिस्तान की नकेल कसे। यदि अमेरिका-चीन की भूमिका सामने आए तो उनके खिलाफ भी स्पष्ट और सख्त रुख दिखाया जाए कि आसेतु हिमालय में न तो किसी की दादागिरी चलेगी और न ही किसी तरह के षड्यंत्र को चलने दिया जाएगा। भारत सरकार इस मुद्दे पर खड़ी रणनीति अपनाए और एकबारगी सख्त सैन्य कार्रवाई करके अपने मजबूत इरादे का परिचय दे, क्योंकि बिनु भय होंहिं न प्रीति...यह बात जगजाहिर है।

वीबी-जी राम जी एक्ट 2025 संरचनात्मक कमियों को ठीक करता है

शिवराज सिंह चौहान

भारत के राष्ट्रपति ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) एक्ट, 2025 को मंज़ूरी दे दी है, जिससे कानूनी मज़दूरी रोज़गार गारंटी को 125 दिन तक बढ़ाया गया है और एक मज़बूत, आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत के लिए सशक्तिकरण, तालमेल और संतृप्ति-आधारित डिलीवरी के ज़रिए ग्रामीण आजीविका को मज़बूत किया गया है।

कुछ लोगों द्वारा गलत समझा जाना- फिर भी, जैसे ही वीबी-जी राम जी एक्ट लागू होता है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ऐसी धारणाएँ बनाई हैं जो ध्यान से जाँच करने पर सही नहीं ठहरतीं। यह दावा किया जा रहा है कि रोज़गार गारंटी कमज़ोर हो गई है, कि बिना सलाह-मशविरे के विकेंद्रीकरण और मांग-आधारित अधिकारों को कमज़ोर किया गया है, और यह कि यह सुधार एक तरह की वित्तीय कटौती है जिसे पुनर्गठन के रूप में छिपाया गया है। इनमें से हर दावा एक्ट के मूल और इरादे को गलत समझने पर आधारित है।

इस गलतफहमी की वजह एक गहरी वैचारिक गलती है - यह मानना कि कल्याण और विकास एक-दूसरे के विरोधी विकल्प हैं। नया फ्रेमवर्क इसके उलट समझ पर आधारित है- कि कल्याण, जो बेहतर कानूनी आजीविका गारंटी पर आधारित है, और विकास, जो टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर आधारित है, एक-दूसरे को मज़बूत करते हैं। इनकम सपोर्ट, संपत्ति निर्माण, कृषि स्थिरता और लंबे समय तक ग्रामीण प्रोडक्टिविटी को एक-दूसरे का विकल्प मानने के बजाय एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। यह सिर्फ़ कोरी बातें नहीं हैं, बल्कि एक ऐसा तरीका है जो कानूनी डिज़ाइन में शामिल है।

यह सुझाव कि रोज़गार के कानूनी अधिकार को कमज़ोर किया गया है, गलत है। यह एक्ट रोज़गार गारंटी के कानूनी और न्यायोचित स्वरूप को बनाए रखता है, साथ ही इसे लागू करने की क्षमता को भी मज़बूत करता है। इसे कम करने के बजाय, अधिकार को 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। प्रक्रियात्मक अयोग्यता के उन प्रावधानों को हटा दिया गया है जो पहले बेरोज़गारी भत्ते को व्यवहार में खत्म कर देते थे, और समय-सीमा वाले शिकायत निवारण तंत्र को मज़बूत किया गया है। यह सुधार सीधे तौर पर कानूनी वादे और ज़मीनी हकीकत के बीच लंबे समय से चली आ रही खाई को दूर करता है।

यह भी तर्क दिया जाता है कि टॉप-डाउन प्लानिंग के पक्ष में डिमांड-बेस्ड रोज़गार को छोड़ दिया गया है। यह एक गलत सोच पर आधारित है। काम की डिमांड मजदूरों से ही आती रहती है। जो बदलता है वह यह है कि अब डिमांड को तभी पूरा नहीं किया जाता जब परेशानी शुरू हो जाती है। पहले से ही काम की प्लानिंग करके, गाँव लेवल पर सबकी भागीदारी वाली प्लानिंग से, यह सुधार यह पक्का करता है कि जब मजदूर रोज़गार ढूंढते हैं, तो काम असल में उपलब्ध हो, न कि एडमिनिस्ट्रेटिव तैयारी की कमी के कारण मना कर दिया जाए। इस मायने में, प्लानिंग डिमांड को दबाती नहीं है; यह उसे लागू करती है।

केंद्रीकरण के आरोप में कानून के ढांचे को नज़रअंदाज़ किया जाता है। ग्राम पंचायतें प्राइमरी प्लानिंग और लागू करने वाली अथॉरिटी बनी हुई हैं, और ग्राम सभाओं के पास लोकल प्लान पर मंज़ूरी देने की शक्तियाँ हैं। जो बदला है वह यह है कि डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग अब अचानक या कभी-कभी नहीं होती, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड और सबकी भागीदारी वाली प्रक्रिया के रूप में संस्थागत हो गई है। विकसित ग्राम पंचायत प्लान को ब्लॉक, ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय लेवल पर इकट्ठा किया जाता है ताकि सभी सेक्टरों में कोऑर्डिनेशन, तालमेल और पारदर्शिता हो सके, न कि लोकल प्राथमिकताओं को नज़रअंदाज़ किया जाए। जो केंद्रीकृत है वह तालमेल है; फ़ैसले लेने का अधिकार लोकल ही रहता है। यह डिसेंट्रलाइज़ेशन को कमज़ोर किए बिना बिखराव को ठीक करता है।

यह दावा कि सुधार बिना किसी सलाह-मशविरे के लागू किए गए, रिकॉर्ड के हिसाब से बिल्कुल गलत है। बिल से पहले राज्य सरकारों के साथ बड़े पैमाने पर बातचीत, टेक्निकल वर्कशॉप और कई स्टेकहोल्डर के साथ चर्चा हुई थी। मुख्य डिज़ाइन फीचर्स - गाँव की प्लानिंग स्ट्रक्चर, कन्वर्जेंस मैकेनिज्म और डिजिटल गवर्नेंस सिस्टम - राज्यों से मिले फीडबैक और सालों के इम्प्लीमेंटेशन से मिले सबक से तैयार किए गए थे।

आवंटन में वृद्धि, समानता- यह व्यापक धारणा कि पिछले एक दशक में रोज़गार गारंटी को व्यवस्थित रूप से कमज़ोर किया गया, तथ्यों से मेल नहीं खाती। बजटीय आवंटन 2013-14 में ?33,000 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ?286,000 करोड़ हो गया। सृजित मानव दिवस 2013-14 तक की अवधि में 1,660 करोड़ से बढ़कर उसके बाद 3,210 करोड़ हो गए। जारी केंद्रीय निधि ?2.13 लाख करोड़ से बढ़कर ?8.53 लाख करोड़ हो गई, और पूरे किए गए कार्य 153 लाख से बढ़कर 862 लाख हो गए। महिलाओं की भागीदारी 48 प्रतिशत से बढ़कर 56.73 प्रतिशत हो गई। अब 99 प्रतिशत से अधिक फंड ट्रांसफर ऑर्डर समय पर जेनरेट होते हैं, और लगभग 99 प्रतिशत सक्रिय श्रमिक आधार पेमेंट ब्रिज से जुड़े हुए हैं। ये रुझान निरंतर प्रतिबद्धता और बेहतर डिलीवरी की ओर इशारा करते हैं, न कि उपेक्षा की ओर।

हालांकि, समय के साथ यह स्पष्ट हो गया कि कार्यान्वयन के अनुभव ने पहले के ढांचे में ही संरचनात्मक कमजोरियों को भी उजागर किया था - सामयिक रोज़गार, बेरोजगारी भत्ते की कमजोर प्रवर्तनीयता, खंडित संपत्ति निर्माण और दोहराव और फर्जी प्रविष्टियों की लगातार गुंजाइश। ये कमजोरियां सूखे के वर्षों, प्रवासन में वृद्धि और कोविड-19 महामारी जैसी व्यवधान की अवधि के दौरान ज़मीनी स्तर पर दिखाई दे रही थीं। नए एक्ट के तहत फिस्कल रिस्ट्रक्चरिंग को भी गलत तरीके से जिम्मेदारी छोड़ने जैसा बताया जा रहा है। केंद्र सरकार का योगदान बढ़ रहा है - केंद्र के हिस्से का प्रावधान ?86,000 करोड़ से बढ़कर लगभग ?295,000 करोड़ हो गया है, जो ग्रामीण रोजगार के लिए लगातार और बढ़े हुए समर्थन को दिखाता है। 60:40 फंडिंग मॉडल केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लंबे समय से चले आ रहे स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जबकि उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों और जम्मू और कश्मीर को 90:10 का अलग अनुपात दिया गया है। फिस्कल विड्रॉल का संकेत देने के बजाय, यह फ्रेमवर्क साझा जिम्मेदारी और जवाबदेही को मजबूत करता है।

पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल, पुडुचेरी विधानसभा चुनावों में कौन मारेगा बाजी?

नीरज कुमार दुबे

साल 2025 भारतीय राजनीति में सत्ताधारी एनडीए के लिये विजय का वर्ष रहा। दिल्ली और बिहार में मिली निर्णायक जीत ने भारतीय जनता पार्टी के आत्मविश्वास को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। दूसरी ओर विपक्ष के लिये यह साल निराशा, विघटन और हताशा का प्रतीक बन गया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पराजित हुई और बिहार में कांग्रेस, राजद और वाम दलों का महागठबंधन लगभग साफ हो गया। लेकिन राजनीति में स्थायी कुछ नहीं होता। 2026 एक नये युद्ध का वर्ष है जहां सत्ता की जड़ें हिलाने के लिए विपक्ष फिर से प्रयास करेगा।

हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। मार्च से मई 2026 के बीच होने वाले इन चुनावों के लिये सभी दल अभी से तलवारें निकाल चुके हैं। अभी से नेताओं के भाषणों में आग है, रणनीतियों में धार है और हर कदम सत्ता की लालसा से भरा हुआ है।

सबसे पहले पश्चिम बंगाल की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस एक मजबूत किले की तरह खड़ी है, लेकिन इस किले की दीवारों पर अब लगातार भगवा हमले हो रहे हैं। 2016 में मात्र तीन सीटों पर सिमटी भाजपा 2021 में 77 सीटों तक पहुंच गयी। यह उछाल संयोग था या स्थायी चुनौती, इसका फैसला 2026 करेगा। ममता बनर्जी 213 सीटों और लगभग आधे वोट प्रतिशत के साथ सत्ता में हैं, लेकिन सत्ता का बोझ भारी होता है। महंगाई, बेरोजगारी और स्थानीय असंतोष अब उनके सामने खड़े बड़े सवाल हैं। भाजपा पूरी ताकत से मैदान में उतर चुकी है और बिहार की जीत के बाद उसका हौसला दोगुना है। वहीं कांग्रेस और वाम दल अपनी खोई हुई जमीन तलाश रहे हैं, लेकिन उनका संकट यह है कि जनता अब उन्हें गंभीर विकल्प मानने को तैयार नहीं है। विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूचियों में हो रहे बदलाव ने बंगाल की राजनीति में आग और घी का काम किया है। अल्पसंख्यक और शहरी क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन चुनावी गणित को पूरी तरह पलट सकते हैं। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो राज्य हमेशा से द्रविड राजनीति का गढ़ रहा है। द्रमुक और अन्नाद्रमुक के बीच सत्ता की रस्साकशी अब एक बार फिर चरम पर है। मुख्यमंत्री स्टालिन के नेतृत्व में द्रमुक मजबूत स्थिति में है, लेकिन सत्ता विरोधी लहर की आहट साफ सुनाई दे रही है। रोजगार, नीट, बिजली दरें और प्रशासनिक अपेक्षाएं सरकार के लिये अग्निपरीक्षा हैं। अन्नाद्रमुक और भाजपा का गठबंधन इस बार ज्यादा संगठित दिख रहा है। अन्नाद्रमुक महासचिव पलानीसामी का दावा है कि यह मोर्चा 200 से अधिक सीटें जीत सकता है। लेकिन इस गणित को सबसे ज्यादा बिगाड़ने वाला नाम है विजय। उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम पहली बार मैदान में है और युवा वर्ग में उसका असर नकारा नहीं जा सकता। हालांकि करूर की भगदड़ की घटना ने विजय की छवि को गहरी चोट पहुंचाई है। वहीं असम को देखें तो राज्य में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा भाजपा के सबसे आक्रामक चेहरों में गिने जाते हैं। 2021 में 75 सीटें जीतने के बावजूद सत्ता विरोधी भावना अब उभर रही है। सरमा का दावा है कि एनडीए 100 से अधिक सीटें जीतेगा, लेकिन राजनीति में दावे अक्सर जमीनी सच्चाई से टकराते हैं। कांग्रेस के लिये यह करो या मरो की लड़ाई है। नये प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई के सामने चुनौती है कि वह लोकसभा चुनावों की सफलता को विधानसभा में बदल सकें। हालांकि दस साल की सत्ता के खिलाफ माहौल बनाना आसान नहीं, खासकर तब जब विपक्षी वोट विभाजित हों। एआईयूडीएफ का रुख यहां निर्णायक साबित हो सकता है। उधर, केरल की राजनीति हमेशा सत्ता परिवर्तन के लिये जानी जाती रही है, लेकिन वाम मोर्चा इस परंपरा को तोड़ चुका है। अब तीसरी बार सत्ता में लौटने का सपना देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन विकास और निरंतरता के नाम पर जनता से समर्थन मांग रहे हैं। वहीं कांग्रेस नीत मोर्चे के लिये यह अस्तित्व की लड़ाई है। यदि इस बार भी नाकामी हाथ लगी तो केरल में कांग्रेस और कमजोर हो जायेगी। भाजपा के लिये भी यह चुनाव अहम है। यदि एक भी सीट वह जीतती है तो केरल की राजनीति में नया अध्याय शुरू होगा।

इस बीच, पुडुचेरी में एनडीए की सरकार अंदरूनी कलह से जूझ रही है। मंत्री का इस्तीफा, दलित असंतोष और गठबंधन की कमजोरी सत्ता को अस्थिर बना रही है। द्रमुक यहां अपनी जड़ें फैलाने की कोशिश में है और कांग्रेस केवल इतना चाहती है कि उसका नाम प्रदेश की राजनीति से न मिटे।

बहरहाल, 2026 के चुनाव सत्ता और विपक्ष, दोनों का इम्तिहान है। यह चुनाव केवल सरकारें नहीं बदलेंगे, यह तय करेंगे कि लोकतंत्र में विकल्प जिंदा हैं या नहीं। देखा जाये तो 2026 का रण सिर्फ सत्ता का नहीं, भविष्य का है।

मनी प्लांट को कांच की बोतल में लगाना शुभ होता है या अशुभ?

मनी प्लांट को घर में लगाना सिर्फ एक साज-सज्जा के लिए ही नहीं, बल्कि यह वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी अहम माना जाता है। इसे कई बार लोग गमले की मिट्टी में लगाते हैं। वहीं, कुछ लोग इसे कांच की बोतल या जार में पानी भरकर भी उगाना पसंद करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार, सही दिशा और दशा में मनी प्लांट लगाना बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं, इसे सुख-समृद्धि और धन आगमन का प्रतीक माना जाता है। वहीं, कांच की बोतल में मनी प्लांट लगाना शुभ होता है या अशुभ, इस बारे में कई लोग जानना चाहते हैं। तो आइए इस लेख में ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद त्रिपाठी से विस्तार से जानते हैं।

वास्तु शास्त्र और फेंगशुई के अनुसार, मनी प्लांट को पानी में कांच की बोतल में लगाना शुभ माना जाता है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और आर्थिक समृद्धि लाने में सहायक होता है। हालांकि, कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना जरूरी है, वरना यह अशुभ प्रभाव भी डाल सकता है।

कांच की बोतल में मनी प्लांट लगाने के लाभ

धन और समृद्धि - मनी प्लांट को उत्तर-पूर्व या दक्षिण-पूर्व दिशा में रखने से घर में धन की वृद्धि होती है।
सकारात्मक ऊर्जा - यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर में शांति बनाए रखता है।
कम मेंटेनेंस - मिट्टी की तुलना में पानी में इसे उगाना आसान होता है, और यह जल्दी बढ़ता है।
घर की सुंदरता बढ़ाता है - कांच की बोतल में यह देखने में आकर्षक लगता है और इंटीरियर को भी खूबसूरत बनाता है।

मनी प्लांट लगाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

पानी साफ रखें - गंदा या बदबूदार पानी रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। हर 4-5 दिन में पानी बदलें।
सूखी या पीली बेल न रखें - अगर पत्तियां सूख रही हैं, तो तुरंत हटा दें, वरना यह नकारात्मकता ला सकती हैं।
कटी-फटी बोतल न रखें - टूटी या फटी कांच की बोतल रखने से घर में अशुभ प्रभाव आ सकता है।

मनी प्लांट को पानी में लगाने का सही तरीका

- किसी पारदर्शी कांच की बोतल या जार का चुनाव करें।
- इसमें साफ पानी डालें और हर 4-5 दिन में पानी बदलते रहें।
- मनी प्लांट की बेल को बोतल में डालें और इसे ऐसी जगह रखें, जहां प्राकृतिक रोशनी आती हो लेकिन सीधी धूप न पड़े।
- चाहें तो पानी में थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइजर मिला सकते हैं, जिससे पौधा तेजी से बढ़ेगा।

क्या शंखनाद से प्रसन्न होते हैं भगवान, पूजा के समय क्या है इसका महत्व

हिंदू धर्म में शंखनाद का विशेष महत्व होता है। किसी भी पूजा के आरंभ और समापन के दौरान शंखनाद करना बहुत शुभ माना जाता है। शंख न केवल धार्मिक अनुष्ठानों का एक अभिन्न हिस्सा है, बल्कि इसे सौभाग्य, शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक भी कहा जाता है। मान्यता है कि पूजा के दौरान शंख की ध्वनि करने से आस-पास की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं और वातावरण में सकारात्मकता का संचार होता है। शास्त्रों की मानें तो जब घर पर शंख बजता है, तो उसकी ध्वनि से देवता प्रसन्न होते हैं और भक्तों को उनका आशीर्वाद मिलता है। इन्हीं कारणों से मंदिरों में आरती और पूजा के समय शंख बजाने की परंपरा है। शंखनाद का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी विशेष महत्व है।

इसकी ध्वनि से वायुमंडल में कंपन उत्पन्न होता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक वातावरण बनता है। साथ ही, शंख मन को एकाग्र करने और ध्यान की स्थिति को प्रबल करने में भी सहायक होता है। धार्मिक ग्रंथों में भी शंखनाद को कल्याणकारी और अशुभ शक्तियों को दूर करने वाला बताया जाता है। इसलिए, पूजा-पाठ, हवन और अन्य धार्मिक कार्यों में शंख बजाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है।

शंख का धार्मिक महत्व

शंख को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है और यह हर धार्मिक अनुष्ठान एवं पूजा का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार, पूजा की शुरुआत शंख ध्वनि से करने से उस स्थान के आस-पास की नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और देवताओं का आह्वान होता है, जिससे वातावरण पवित्र एवं सकारात्मक बना रहता है। इसी कारण से भगवान कृष्ण ने भी अपने दिव्य शंख पांचजन्य को महाभारत युद्ध के दौरान बजाकर पांडवों का उत्साहवर्धन किया था। वहीं, ज्योतिष में मान्यता यह भी है कि माता लक्ष्मी का वास शंख में होता है, इसलिए इसे घर में या पूजा स्थल पर रखना अत्यंत शुभ माना जाता है और इससे समृद्धि बनी रहती है। शंख बजाने से मानसिक शांति भी मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।

पूजा के समय शंखनाद के लाभ

पूजा के समय शंखनाद करना अत्यंत शुभ और लाभकारी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शंख की पवित्र ध्वनि से देवता प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। यह न केवल ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त करने का माध्यम है, बल्कि घर में शुभता का संचार भी करता है।

शंख बजाने से वातावरण की कई तरह की नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं, जिससे घर में शांति और सुख-समृद्धि बनी रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शंख की ध्वनि से घर के वास्तु दोष समाप्त होते हैं और शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसके नियमित अभ्यास से मानसिक शांति और एकाग्रता भी बढ़ती है, जिससे ध्यान और साधना में सहायता मिलती है। पूजा-पाठ के दौरान शंखनाद करने से न केवल आध्यात्मिक उन्नति होती है, बल्कि यह शरीर और मन को भी ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए, इसे

धार्मिक एवं स्वास्थ्य लाभों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है।

शंख बजाने के नियम

पूजा के समय शंख बजाने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना जरूरी होता है। यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आपको इसका पूर्ण लाभ मिल सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शंख को हमेशा साफ-सुथरे स्थान पर रखना चाहिए और इसे अशुद्ध हाथों से स्पर्श नहीं करना चाहिए। पूजा या किसी भी शुभ कार्य से पहले शंख को गंगाजल से शुद्ध करना शुभ माना जाता है। शंख बजाने का सही समय प्रातःकाल और संध्या का होता है, क्योंकि इस समय शंख की ध्वनि से वातावरण शुद्ध होता है। इसे भगवान की आरती या पूजा के दौरान बजाना भी शुभ माना जाता है, लेकिन इसे रात में बजाने से बचना चाहिए। वैसे तो माना जाता है कि महिलाएं शंख को पूजा में रख सकती हैं और इसकी पूजा भी कर सकती हैं. लेकिन उन्हें शंख बजाने की मनाही होती है। इसके अलावा, शंख में जल भरकर भगवान को अर्पित किया जा सकता है, लेकिन इस जल को पीने या रसोई में उपयोग करने से बचना चाहिए। टूटा या खंडित शंख पूजा में उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। इन नियमों का पालन कर शंख बजाने से आध्यात्मिक लाभ के साथ-साथ मानसिक और शारीरिक शुद्धता भी प्राप्त होती है।

किस समय घर में शंख बजाना चाहिए?

हिन्दू धर्म में शंख बजाने का बहुत महत्व माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शंख की ध्वनि से सकारात्मकता का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा घटने लगती है। इसके अलावा, शंख बजाने से देवी-देवता प्रसन्न होते हैं और घर में दिव्यता एवं सुख-समृद्धि का वास होने लगता है। हालांकि शास्त्रों में शंख बजाने के कई नियम बताये गए हैं जिनमें विधि से लेकर समय तक के बारे में वर्णित है।

कब शंख बजाना चाहिए?

- सूर्योदय से पहले का समय यानी कि ब्रह्म मुहूर्त शंख बजाने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय वातावरण में शांति और सकारात्मक ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। ऐसे में इस समय में शंख बजाने से आसपास की शांति अशांत मन को शांत करती है और सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से व्यक्ति मानसिक पीड़ा से दूर होता है।
- जब भी घर में पूजा या हवन हो, तो शंख बजाना शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान शंख बजाकर देवताओं का आह्वान किया जाता है और देवी-देवताओं की दिव्यता घर में सुख-समृद्धि के रूप आने लगती है। पूजा-पाठ या हवन-अनुष्ठान के दौरान शंख बजाने से पूजा में अगर कोई दोष भी लग जाए हो तो वह भी तुरंत नष्ट हो जाता है।
- पूजा-पाठ या हवन-अनुष्ठान के अलावा त्यौहारों पर भी संख अवश्य बजाना चाहिए। किसी भी शुभ काम की शुरुआत जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, नई नौकरी, नया व्यापार आदि शंख बजाकर ही करनी चाहिए। इससे शुभ कार्यों में सफलता मिलती है। निर्विघ्न काम पूरे हो जाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा काम में बाधाएं नहीं पैदा कर पाती है।
- शंख बजाने के दिन की बात करें तो यूं तो रोजाना शंख बजाना उत्तम माना जाता है लेकिन अगर किसी कारण से आपके लिए रोजाना शंखनाद करना संभव न हो तो आप मंगलवार और शुक्रवार के दिन पूजा के दौरान शंख बजा सकते हैं। मंगलवार के दिन शंखनाद से विवाह की बाधाएं नष्ट होती हैं और शुक्रवार के दिन शंखनाद से धन में वृद्धि होती है।

क्या शंखनाद से ईश्वर प्रसन्न होते हैं?

शंखनाद को हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, जब शंख बजाया जाता है, तो उसकी दिव्य ध्वनि से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। शास्त्रों में भी इस बात का वर्णन मिलता है कि देवताओं के पूजन और यज्ञों में शंख ध्वनि का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसकी गूंज से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और वातावरण शुद्ध बनता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से जुड़े होने के कारण शंख को विशेष रूप से पूजनीय माना जाता है। जब पूजा के दौरान शंखनाद किया जाता है, तो यह भगवान का आह्वान करने का प्रतीक होता है, जिससे वे भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करते हैं। किसी भी पूजा की पूर्णता शंखनाद से मानी जाती है और इसका जीवन में विशेष महत्व होता है।

नीलम धारण करने से पहले कुंडली का विचार करना जरूरी

ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार नीलम रत्न व्यक्ति को रंक से राजा बना सकता है। यह रत्न शनिदेव को समर्पित होता है। इस रत्न को हर कोई धारण नहीं कर सकता है। जहां ये रत्न रंक से राजा बना देता है वहीं अशुभ होने पर ये रत्न राजा को भी रंक बना सकता है। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार नीलम रत्न को धारण करने से पहले कुंडली का विचार करना जरूरी होता है। .

नीलम रत्न के फायदे

- जिन लोगों के लिए नीलम शुभ होता है उन्हें इसका तुरंत फायदा दिखने लगता है।
- स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है।
- धन- लाभ होने लगता है।
- नौकरी और व्यापार में तरक्की होने लगती है।
- शनि की वक्री चाल से इन राशियों को हो रहा है फायदा, जानें क्या आप भी हैं इस लिस्ट में शामिल

नीलम रत्न के अशुभ होने पर इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है

- नीलम हर किसी को शुभ फल नहीं देता है। जिन लोगों के लिए ये शुभ नहीं है, उन्हें स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
- धन- हानि हो सकती है।
- कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है।

ऐसे करें पहचान नीलम आपके लिए शुभ है या नहीं

नीलम रत्न को धारण करने से पहले उसको तकीया के नीचे रखकर सोएं। अगर आपको रात में कोई भी बुरा स्वप्न नहीं आता है और अच्छी गहरी नींद आती है तो इसका मतलब है ये रत्न आपके लिए शुभ है। अगर आपको अच्छी और गहरी नींद नहीं आती है तो इस रत्न को धारण न करें। रत्न धारण करने के बाद अशुभ घटना होने पर इस रत्न को तुरंत उतार दें।

क्या खाली शंख घर या मंदिर में रखना सही है?

हिन्दू धर्म शास्त्रों में शंख को माता लक्ष्मी का बड़ा भाई माना गया है। इसके अलावा, शंख की पूजा का भी विधान मौजूद है। इसी कारण से न सिर्फ घर या घर के मंदिर में लोग शंख रखते हैं बल्कि उसकी पूजा भी करते हैं। हालांकि शास्त्रों में घर या मंदिर में शंख रखने से जुड़े कई नियम भी बताये गए हैं जिनका पालन आवश्यक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि घर या घर के मंदिर में शंख रखने से घर की बरकत बनी रहती है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि लोग शंख लाकर उसे यूं ही रख देते हैं यानी कि शंख को खाली स्थापित कर देते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या खाली शंख घर या घर के मंदिर में रखना चाहिए। घर या घर के मंदिर में शंख रखने से सकारात्मकता का संचार होता है, लेकिन अगर घर या मंदिर में खाली शंख रखा है तो इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और शंख की शुभता एवं दिव्य ऊर्जा खत्म हो जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि शंख को हमेशा शुद्ध जल से भरकर रखना चाहिए। इसके अलावा, शंख को पुष्प से भरकर भी रखा जा सकता है। शंख में जल भरकर रखने से घर में बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती हैं। वहीं, शंख में फूल भरकर रखने से घर में पारिवारिक शांति बनी रहती है और घर में परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल बेहतर बनता है एवं मधुरता पनपने लगती है। शंख में फूल भरकर रखने से ग्रह दोष भी दूर होता है।

मुनीर की बेकद्री से पाकिस्तान से भाग रहा टैलेंट

इस्लामाबाद , एजेंसी।
पाकिस्तान आज उस मोड़ पर खड़ा है, जहां देश की सबसे बड़ी पूंजी उसकी प्रतिभा तेजी से हाथ से फिसलती जा रही है। बिगड़ती अर्थव्यवस्था, राजनीतिक अराजकता और अस्थिर शासन के बीच पाकिस्तान बीते दो वर्षों में अपने हजारों डाक्टरों, इंजीनियरों और अकाउंटेंट्स को खो चुका है। इसे महज पलायन नहीं, बल्कि एक गंभीर राष्ट्रीय संकट कहा जाए तो गलत नहीं होगा।

पाकिस्तान सरकार की ही एक ताजा रिपोर्ट ने इस सच्चाई पर मुहर लगा दी है। आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 महीनों में देश से करीब पांच हजार डाक्टर, 11,000 इंजीनियर और 13,000 अकाउंटेंट्स देश के बाहर चले गए। इन आंकड़ों के सामने सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ब्रेन गेन वाला दावा खोखला साबित होता दिख रहा है।

आंकड़े बनाम बयानबाजी

हाल ही में विदेशों में बसे पाकिस्तानियों को संबोधित करते हुए आसिम मुनीर ने बड़े पैमाने पर हो रहे पलायन को ब्रेन ड्रेन (कुशल

2 साल में 5 हजार डॉक्टर व 11000 इंजीनियर गए बाहर

पेशेवर का अपने देश से दूसरे देश में पलायन) मानने से इनकार किया था। लेकिन पूर्व पाकिस्तानी सीनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने इन आंकड़ों को साझा करते हुए कहा कि राजनीति सुधरेगी तभी अर्थव्यवस्था सुधरेगी। उन्होंने यह भी बताया कि पाकिस्तान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा फ्रीलांसिंग हब होने के बावजूद इंटरनेट शटडाउन से 1.62 अरब डालर का नुकसान झेल चुका है और 23.7 लाख फ्रीलांसिंग नौकरियां खतरे में हैं।

पलायन के आंकड़े दे रहे चेतावनी

पाकिस्तान के प्रवासी कल्याण एवं विदेशी रोजगार ब्यूरो के आंकड़े भी हालात की गंभीरता दिखाते हैं। 2024 में 7.27 लाख और 2025 में नवंबर तक 6.87 लाख पाकिस्तानियों ने विदेश में रोजगार के लिए पंजीकरण कराया। चिंता की बात यह है कि अब यह पलायन केवल मजदूरों तक सीमित नहीं, बल्कि उच्च शिक्षित और कुशल पेशेवर भी देश छोड़ रहे हैं। हैं। कई लोगों ने इसे हकीकत से आंख मूंदने वाला दावा बताया है। साफ है कि पाकिस्तान में बयान और सच्चाई के बीच की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है, जो देश के भविष्य को और अनिश्चित बना रही है।

मेडिकल क्षेत्र पर सबसे गहरी चोट

सबसे गहरी चोट मेडिकल क्षेत्र को लगी है। 2011 से 2024 के बीच नर्सों के पलायन में 2144 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसका सीधा असर पाकिस्तान की कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ रहा है। घबराई शहबाज शरीफ सरकार ने एयरपो?र्ट्स पर सख्ती बढ़ाई है। 2025 में अब तक 66,154 यात्रियों को विदेश जाने से रोका गया, जो पिछले साल से लगभग दोगुना है। इसके साथ ही, अवैध प्रवास और भीख मांगने के आरोप में हजारों पाकिस्तानियों को विदेशों से डिपोर्ट किया गया है। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने पेशेवर भिखारियों और अधूरे दस्तावेज वालों पर विदेश यात्रा प्रतिबंध का ऐलान भी किया है। इन तमाम घटनाओं के बीच इंटरनेट मीडिया पर आसिम मुनीर के ब्रेन गेन बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई।

जरदारी बोले- पाकिस्तान दोबारा युद्ध को तैयार

● मई में भारत को समझाया युद्ध बच्चों का खेल नहीं

कराची, एजेंसी।
पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने शनिवार को कहा कि मई में हुए युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने भारत के आक्रमण का मजबूती से जवाब दिया। इसके बाद भारत सरकार को समझ आ गया कि युद्ध बच्चों का खेल नहीं है।

जरदारी शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की पुण्यतिथि पर कराची में एक रैली में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान के संयम के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान चाहता तो और भी भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया जा सकता था। जरदारी ने कहा, मोदी अब समझ चुके हैं कि पाकिस्तान अपनी रक्षा करना जानता है। अगर दोबारा युद्ध थोपा गया तो पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है। इधर, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टीके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ की। उन्होंने कहा- हमारे फील्ड मार्शल (आसिम मुनीर) का नाम सुनते ही मोदी छिप जाते हैं। अब विदेश में पाकिस्तान को लेकर कुछ नहीं कहते। वहीं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया कि मई में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान की जीत हुई थी।

मैराथन दौड़ने से लंबे समय तक दिल रहता है जवान

नई स्टडी में खुलासा

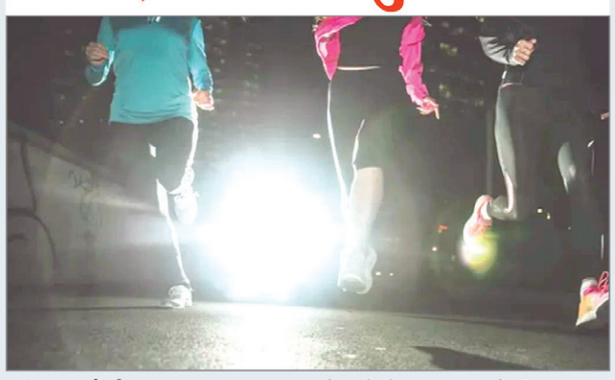

लंदन, एजेंसी।
मैराथन दौड़ को अकसर संदेह की नजर से देखा जाता है। लोगों को लगता है कि घंटों तक दौड़ते हुए पैर थक जाते हैं, सांसें तेज हो जाती हैं और दिल लगातार कड़ी मेहनत करता है। वर्षों से यह सवाल उठता रहा है कि 42 किलोमीटर की मैराथन दौड़ कहीं दिल को स्थायी नुकसान तो नहीं पहुंचाती।

अब इस बहस पर एक दशक लंबे वैज्ञानिक अध्ययन ने काफी हद तक विराम लगा दिया है। जर्नल जामा कार्डियोलाजी में प्रकाशित एक नए अध्ययन में 152 शौकिया मैराथन धावकों को शामिल किया गया। शोधकर्ताओं ने धावकों के दिल की जांच दौड़ से पहले और बाद में की और फिर अगले दस वर्षों तक उनके हृदय स्वास्थ्य पर नजर रखी। अध्ययन में पाया गया कि मैराथन के तुरंत बाद दिल के दाहिने हिस्से (राइट वेंट्रिकल), जो फेफड़ों तक खून पंप करता है, की पंपिंग क्षमता में अस्थायी कमी आती है। हालांकि यह प्रभाव कुछ ही दिनों में सामान्य हो जाता है। नए अध्ययन में टूटी पुरानी धारणाएं सबसे अहम बात यह सामने आई कि दस साल की अवधि में इन धावकों के दिल में किसी तरह की स्थायी क्षति के संकेत नहीं मिले। शोध बताते हैं कि मैराथन के दौरान दिल के दाहिने हिस्से पर अधिक दबाव पड़ता है, क्योंकि फेफड़ों में रक्त प्रवाह के लिए दबाव बढ़ जाता है। इसी कारण यह हिस्सा अस्थायी रूप से फैल सकता है और कम प्रभावी हो सकता है, लेकिन आराम के बाद स्थिति सामान्य हो जाती है। असहज लगे तो डाक्टर से परामर्श जरूरी हालांकि विशेषज्ञ यह भी चेतावनी देते हैं कि मैराथन दौड़ पूरी तरह जोखिम-मुक्त नहीं है। यह छिपी हुई हृदय बीमारियों, खासकर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, को उजागर कर सकती है। दौड़ के दौरान या बाद में सीने में दर्द, असामान्य सांस फूलना या चक्कर आता हो, तो तुरंत चिकित्सकीय जांच जरूरी है। यह निष्कर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले के कुछ अध्ययनों में आशंका जताई गई थी कि लंबे समय तक अत्यधिक सहनशक्ति वाली कसरत से दिल को नुकसान हो सकता है। इन चिंताओं की एक बड़ी वजह मैराथन के बाद खून में ट्रोपोनिन नामक तत्व का बढ़ना रहा है। आमतौर पर ट्रोपोनिन का स्तर बढ़ना हार्ट अटैक का संकेत माना जाता है, क्योंकि यह तब निकलता है जब हृदय की मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है। मैराथन के बाद कई धावकों में ट्रोपोनिन का स्तर बढ़ा हुआ पाया जाता है, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है। मैराथन जैसे लंबे धीरज वाले व्यायाम के बाद ट्रोपोनिन बढ़ सकता है, लेकिन यह किसी हृदय रोग का संकेत नहीं होता।

यह सपना नहीं, बांग्लादेश के लिए योजना...,

● 17 साल बाद वतन वापसी पर तारिक रहमान ने लिखा खुला पत्र

ढाका, एजेंसी।
बांग्लादेश की राजनीति में एक भावनात्मक और ऐतिहासिक पल तब देखने को मिला, जब पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और शहीद राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे तथा बीएनपी नेता तारिक रहमान ने 17 वर्षों बाद देश वापसी के बाद बांग्लादेश की जनता के नाम एक खुला पत्र लिखा। यह पत्र उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर साझा किया। मिट्टी पर लौटना उनके जीवन का सबसे भावुक क्षण है। उन्होंने कहा कि ढाका की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब, लोगों की दुआएं और अपनापन वह कभी नहीं भूल पाएंगे। उन्होंने जनता के प्यार और सम्मान के लिए आभार जताते हुए कहा कि यह स्वागत उनके और उनके परिवार के लिए अविस्मरणीय है। अपने भविष्य के विजन को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि उनका सपना नहीं, बल्कि एक ठोस योजना है एक ऐसा बांग्लादेश जहां शांति, गरिमा और सुरक्षा हो और हर बच्चे को बेहतर भविष्य की उम्मीद मिले।

सभी बांग्लादेशियों का जताया आभार

तारिक रहमान ने अपने समर्थकों, नागरिक समाज, युवाओं, किसानों, श्रमिकों और विभिन्न पेशेवर वर्गों का धन्यवाद करते हुए कहा कि बांग्लादेश की असली ताकत उसकी एकजुट जनता में है। उन्होंने मीडिया की भूमिका की भी सराहना की और सुरक्षा व्यवस्था संभालने वाले प्रशासनिक तंत्र को धन्यवाद दिया। पत्र में उन्होंने अन्य राजनीतिक दलों और आंदोलनों के नेताओं के प्रति भी आभार जताया, जिन्होंने उनकी वापसी का स्वागत किया। तारिक रहमान ने लोकतंत्र, बहुदलीय व्यवस्था और बदले की राजनीति से ऊपर उठकर शांतिपूर्ण राजनीतिक संस्कृति की जरूरत पर जोर दिया। तारिक रहमान गुरुवार को ढाका लौटे, जहां उनकी पार्टी के हजारों समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वह अपनी पत्नी जुबैदा और बेटी जाइमा के साथ ढाका पहुंचे।

सीट-बंटवारे को लेकर जमात के साथ समझौते की तैयारी कर रही एनसीपी

ढाका , एजेंसी। बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में आम चुनाव होने वाले हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के खिलाफ 2024 के छात्र-नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों से उभरी नेशनल सिटीजन पार्टी (एनसीपी) चुनावों से पहले एक मजबूत राजनीतिक आधार स्थापित करने के लिए कथित तौर पर संघर्ष कर रही है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, एनसीपी अब सीट-बंटवारे को लेकर जमात-ए-इस्लामी के साथ एक संभावित समझौते की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। जिन छात्रों ने मुहम्मद यूनुस को अंतरिम प्रशासन के प्रमुख के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्हीं छात्रों द्वारा गठित इस पार्टी के बारे में व्यापक रूप से माना जाता है कि इसे यूनुस का संरक्षण प्राप्त है। प्रारंभ में एनसीपी को बांग्लादेश के पारंपरिक सत्ता केंद्रों - बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और जमात-ए-इस्लामी - से इतर एक तीसरी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरने के महत्वाकांक्षी प्रयास के रूप में देखा गया था। गौरतलब है कि वर्षों तक देश की राजनीति में प्रभुत्व रखने वाली अवामी लीग को अंतरिम सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। बहरहाल, इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर अच्छी-खासी मौजूदगी के बावजूद एनसीपी कथित तौर पर डिजिटल लोकप्रियता को जमीनी समर्थन में तब्दील करने में नाकाम रही है।

12 घंटे में 1000 से ज्यादा पुरुषों से बनाए संबंध

● महिला ने खुद कबूला...

लंदन, एजेंसी। ब्रिटेन की विवादास्पद एडल्ट कंटेंट क्रिएटर बॉनी ब्लू उर्फ टिया बिलिंगर को इंडोनेशिया ने बाली से डिपोर्ट कर दिया है। अधिकारियों ने उन पर कम से कम 10 साल के लिए इंडोनेशिया में दोबारा प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस कार्रवाई के बाद बॉनी ब्लू एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में आ गई हैं। वह पहले भी 2025 की शुरुआत में 12 घंटे में 1,057 पुरुषों के साथ संबंध बनाने के दावे को लेकर चर्चा में रही थीं।

ब्रिटेन की विवादास्पद एडल्ट कंटेंट क्रिएटर बॉनी ब्लू उर्फ टिया बिलिंगर को इंडोनेशिया ने बाली से डिपोर्ट कर दिया है। अधिकारियों ने उन पर कम से कम 10 साल के लिए इंडोनेशिया में दोबारा प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। शुक्रवार को हुई इस कार्रवाई के बाद बॉनी ब्लू एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में आ गई हैं। वह पहले भी 2025 की शुरुआत में 12 घंटे में 1,057 पुरुषों के साथ संबंध बनाने के दावे को लेकर चर्चा में रही थीं।

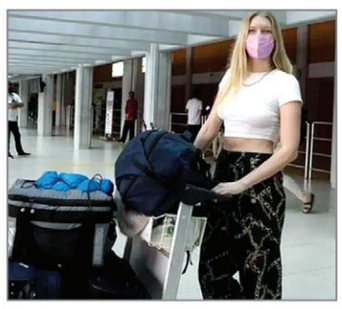

बॉनी ब्लू इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और फिजी से भी विवादों के चलते डिपोर्ट की जा चुकी हैं। ताजा मामला बाली का है, जहां वह एक नीले पिकअप ट्रक में घूमते हुए कथित तौर पर एडल्ट कंटेंट शूट कर रही थीं। एक ÷जिम्मेदार नागरिक÷ की शिकायत पर पुलिस ने एक स्टूडियो पर छापा मारा, जहां बॉनी के साथ तीन अन्य पुरुष- दो ब्रिटिश और एक ऑस्ट्रेलियाई- भी मौजूद थे। शुरुआत में मामला इंडोनेशिया के सख्त पोर्नोग्राफी कानूनों के तहत दर्ज किया गया, जिसमें 15 साल तक की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि जांच के दौरान बॉनी ब्लू के खिलाफ पोर्नोग्राफी से जुड़ा ठोस सबूत नहीं मिला। इसके बाद मामला टूरिस्ट वीजा के दुरुपयोग और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन तक सीमित रह गया। उन पर बिना लाइसेंस ड्राइविंग और वाहन के रजिस्ट्रेशन न होने जैसे आरोप तय किए गए। अदालत ने मामूली जुर्माना लगाया और डिपोर्टेशन का आदेश दिया। इमिग्रेशन प्रमुख हेरु विनारको ने कहा कि बॉनी छुट्टियां मनाने के लिए आई थीं, लेकिन उन्होंने वीजा शर्तों का उल्लंघन कर काम किया। अदालत से बाहर निकलते समय बॉनी को कैमरों के सामने मुस्कुराते और किस उड़ाते हुए भी देखा गया।

जेएसडब्लू एमजी मोटर इंडिया ने अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक्सटेंडेड एश्योर्ड बायबैक प्रोग्राम पेश किया

नईदिल्ली। आज जेएसडब्लू एमजी मोटर इंडिया ने अपने इलेक्ट्रिक वाहनों पर एश्योर्ड बाय बैक प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की, ताकि ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना और अधिक आसान व सुगम हो सके। इस घोषणा के बाद जेएसडब्लू एमजी मोटर इंडिया देश का पहला कार ब्रांड बन गया है, जो अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मौजूदा 3 साल से 5 साल तक की अवधि के लिए एश्योर्ड बायबैक प्रदान कर रहा है। इस प्रोगाम द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन के खरीदारों को निर्धारित अवधि के बाद अपने वाहन के लिए फिक्स्ड रिसेल वैल्यू मिल सकेगी।

इस नए व अद्वितीय प्रोग्राम के माध्यम से एमजी इलेक्ट्रिक वाहन के मालिकों को चयनित प्लान के आधार पर 3 साल, 4 साल या 5 साल के बाद गारंटीड रिसेल वैल्यू प्राप्त होगी। इस प्रोग्राम ने एमजी मोटर की मौजूदा पेशकशों को मजबूत बनाया है, जिसके अंतर्गत स्वामित्व के 3 सालों के बाद 60त्न तक की बाय-बैक वैल्यू की गारंटी मिलेगी। इसका संचालन किसी भी लोन या फाईनेंस स्कीम से अलग स्वतंत्र रूप से होगा। देश में पहली बार कमर्शियल एमजी जैड एस इलेक्ट्रिक वाहनों के मालिक अपने 3 साल तक पुराने एमजी वाहनों पर रिसेल के लाभ प्राप्त कर सकेंगे तथा उन्हें प्रतिवर्ष 60,000 रुपये तक का माईलेज मिलेगा। इस इनोवेटिव बायबैक प्रोग्राम के बारे में जेएसडब्लू एमजी मोटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर, अनुराग महरोत्रा ने बताया कि ''एमजी ने एक ग्राहक केंद्रित ब्रांड के रूप में बी-ए-ए-एस (बैटरी एज़ ए सर्विस) औरई.वी बैटरी पर लाईफटाईम वॉरंटी जैसे प्रोग्रा पेश किए हैं, ताकि ई.वी का स्वामित्व मोबिलिटी का बेहतरीन अनुभव प्रदान करे। ई.वी के खरीददार रिसेल वैल्यू को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। लॉकटन इंडिया इंश्योरेंस ब्रोकिंग एंड एडवाईज़री लिमिटेड द्वारा जुनो जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी में पेश किए जा रहे हमारे एमजी वैल्यू प्रॉमिज़ प्रोग्राम (एश्योर्ड बायबैक) के माध्यम से हम एमजी के मालिकों को 3 से 5 साल की अवधि के लिए एश्योर्ड रिसेल वैल्यू प्रदान कर रहे हैं, ताकि ग्राहक पूरे सुकून के साथ एमजी इलेक्ट्रिक वाहन खरीद सकें। हमारा मानना है कि यह अभियान से भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का विस्तार करने में मुख्य भूमिका निभाएगा तथा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों की एक मुख्य चिंता दूर होगी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में उनका विश्वास बढ़ेगा।'' इस प्रोग्राम से ग्राहकों को अनेक लाभ मिलेंगे। यह भारत में व्यापक ई.वी सेगमेंट में अपनी तरह का पहला प्रोग्राम है, जो किसी भी फाईनेंस या लोन प्रोग्राम से जुड़ा नहीं है। इस प्रोग्राम की मदद से डेप्रिसिएशन का जोखिम कम हो जाएगा और ग्राहक आसानी से नए एमजी मॉडल में अपग्रेड कर सकेंगे। इससे वो यह निर्णय आसानी से ले सकेंगे कि उन्हें अपना एमजी वाहन आगे भी अपने साथ रखना है या उसे रिटर्न करना है, या फिर वो नए एमजी वाहन में अपग्रेड भी कर सकेंगे। ग्राहकों को चयनित अवधि के बाद अपने एमजी वाहन को अपने पास रखने, उसे लौटाने या बदलने का अवसर मिलेगा। यह प्रोग्राम डेप्रिसिएशन की चिंता को दूर करता है तथा खरीददारों का विश्वास स्थापित करता है, जिससे भारत में ई.वी अपनाने में तेजी आएगी। इससे ग्राहकों को बेहतर वित्तीय अनुमान, सुविधा और लंबे समय तक मन की शांति प्राप्त हो सकेंगे। शनाय घोष, एमडी एवं सीईओ, जुनो जनरल इंश्योरेंस ने कहा, ''एक डिजिटल बीमाकर्ता के रूप में इस साझेदारी से एक मजबूत एवं भविष्य के लिए तैयार ई.वी इंश्योरेंस पोर्टफेलियो का निर्माण करने का हमारा लक्ष्य मजबूत होगा। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी भारत में परिवहन के तरीके में परिवर्तन लेकर आ रही है।

चीन में अंतरिक्ष मिशन से लौटने के बाद मादा चूहे ने बच्चों को दिया जन्म

बीजिंग , एजेंसी। चीन के अंतरिक्ष स्टेशन पर हाल ही में भेजे गए एक मिशन में शामिल चार चूहों में से एक मादा चूहे ने पृथ्वी पर स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, चार चूहों (दो नर और दो मादा) को 31 अक्टूबर को अंतरिक्ष में भेजा गया था। 14 नवंबर को पृथ्वी पर लौटने से पहले उन्हें अंतरिक्ष स्टेशन पर एक विशेष आवास में रखा गया था। 10 दिसंबर को दिया बच्चों को जन्म वापसी के बाद, एक मादा चूहे ने गर्भधारण किया और 10 दिसंबर को नौ बच्चों को जन्म दिया। इनमें से छह नवजात जीवित हैं, जो एक सामान्य दर मानी जाती है। मादा चूहा सामान्य रूप से अपने बच्चों को दूध पिला रही है और बच्चे सक्रिय और स्वस्थ हैं। चीनी विज्ञान अकादमी के प्राणी विज्ञान संस्थान की शोधकर्ता वांग होंगमेई ने कहा, मिशन ने दिखाया कि अल्पकालिक अंतरिक्ष यात्रा से चूहे की प्रजनन क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता है। उन्होंने आगे कहा, ÷यह स्तनधारियों के प्रारंभिक विकास चरणों पर अंतरिक्ष वातावरण के प्रभाव की जांच के लिए अमूल्य नमूने भी प्रदान करता है।

कनाडा के गुरुद्वारे से पाठी का इमोशनलः कहा-

टोकाटाकी-भेदभाव से तंग हूं, कोई पैसे देता है तो ताने मारते हैं; जल्द इंडिया लौटूंगा

टोरंटो, एजेंसी।
कनाडा के गुरुद्वारा से पाठी सिंह की इमोशनल वीडियो सामने आई है। इसमें पाठी सिंह ने कनाडा के गुरुद्वारे पर भेदभाव और टोकाटाकी के आरोप लगाए हैं। कीर्तन करते हुए रागी जत्थे में शामिल सिंह इमोशनल होकर कहते हैं कि मैं अब टोकाटाकी के इस कल्चर में ज्यादा दिन नहीं रह पाऊंगा। यहां तो बोलने की आजादी भी छीन ली गई है।

उन्होंने कहा कि हमें क्या बोलना है, किसके लिए अरदास करनी है, किसके लिए नहीं, किससे सिरोपा लेना है और किसको सिरोपा देना है, जैसी बातों पर कंट्रोल किया जाता है। सिंह ने गुरुद्वारों की सैलरी पर भी सवाल उठाया।

उन्होंने कहा कि यहां महीने के 800 डॉलर दिए जा रहे हैं। अगर हमें संगत में से कोई पैसे दे जाता है तो ताने सुनने को मिलते हैं कि बहुत कमाई कर रहे हो। आपको तो बिना मेहनत के ही पैसे मिल रहे हैं। मैं तंग आ चुका हूं और अब कनाडा से परमानेंट इंडिया जा रहा हूं।

गुरुद्वारों पर भेदभाव के आरोप नए नहीं हैं। शुक्रवार को श्री फतेहगढ़ साहिब में हुई शहीदी सभा में ये मुद्दा निहंग सिंह भी उठा चुके हैं। उन्होंने कहा था कि 2-2 बाटों से गुरुद्वारों में अमृत छकाया जा रहा है। एक बाटा किसी जात का तो दूसरा किसी जात है। जात-पात खत्म नहीं हो पाई है। गुरुघर में हर बात पर टोका जाता है- सिंह ने कहा कि संगत के चरणों में विनती है कि मुझे यहां ड्यूटी करते हुए ढाई साल हो गए हैं और अब मैं यहां से पक्की छुट्टी लेना चाहता हूं। क्योंकि हर बात पर हमें टोका जाता है। ऐसी छोटी-छोटी बातों पर हमें घेरा जाता है, जिन पर बच्चे भी नहीं लड़ते। पता नहीं आज ये कैसे गुरुघर बन गए हैं कि हमें छोटी-छोटी बात पर सेवादारों को दोषी ठहराते हैं। सिरोपा उसने क्यों नहीं लिया, वह चंवर सेवा नहीं करेगा, उसने जयकारा क्यों लगाया जैसी बातों पर टोका-टोकी होती है। हमारी गलतियां क्या हैं? क्या हम यहां अपनी बेइज्जती कराने के लिए आए हैं। अरदास के समय भी हमें टोका जाता है कि आप यह नहीं बोलेंगे। ये नहीं बोलेंगे या वो नहीं बोलेंगे। क्या ये लोग हमें बताएंगे कि हमें अपना काम कैसे करना है।

खबर-खास

कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने जनदर्शन में सुनी आमजनों की मांग एवं समस्याएं

जांजगीर-चांपा (समय दर्शन)। कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित जनदर्शन के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याएँ एवं मांगों को गंभीरतापूर्वक सुना। उन्होंने प्राप्त आवेदनों का संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्रत्येक प्रकरण का समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आज जनदर्शन में कुल 55 आवेदन प्राप्त हुए है।

जनदर्शन में आज तहसील पामगढ़ के ग्राम मेऊ निवासी श्रीमती धनेश्वरी यादव द्वारा आर्थिक सहायता राशि दिलाने, तहसील मुख्यालय जांजगीर निवासी श्री संजय गोपाल द्वारा राजस्व प्रकरण की नकल दिलाने, ग्राम खैरा निवासी श्रीमती भूरीबाई द्वारा अपने भूमि की फौती व नामांतरण करवाने, तहसील बलौदा के ग्राम जर्वे ब के निवासी श्रीमती दिलबाई द्वारा सीमांकन करवाने, तहसील बम्हनीडीह के ग्राम बोरसी निवासी श्री लोचन खुटे ने श्रम पंजीयन में जन्मतिथि की त्रुटि सुधार करवाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किये। कलेक्टर श्री महोबे ने प्राप्त सभी आवेदनों का संबंधित अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्यवाही करते हुए निराकरण करने के निर्देश दिए हैं।

मृतकों के परिजनों को मिली 12 लाख रूपए की आर्थिक सहायता

दुर्ग (समय दर्शन)। कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 12 लाख रूपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड नं. 08 ग्राम व पो. निकुम तहसील व जिला दुर्ग निवासी श्रीमती रामेश्वरी साहू की विगत 21 मई 2025 को आंधी तूफान से नीलगिरी का पेड़ इनके ऊपर गिरने से इनकी मृत्यु हो गई थी। इसी प्रकार ग्राम पुरई तहसील व जिला दुर्ग के श्री विक्रम सिंह की विगत 04 मई 2025 को नहाते वक्त तालाब के पानी में डूबने से एवं वार्ड नं. 04 गयाबाई विद्यालय के पास गया नगर दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग निवासी श्री समीर सिंह की विगत 06 सितंबर 2024 को नदी में डूबने से मृत्यु हुई थी। कलेक्टर द्वारा शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के प्रावधानों के अनुरूप स्व. श्रीमती रामेश्वरी साहू के पति श्री रिखी राम साहू, स्व. श्री विक्रम सिंह के पिता श्री यशवंत सिंह और स्व. श्री समीर सोनी की पत्नी श्रीमती नीतू सोनी को 4-4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

नवनियुक्त कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं ने साप्ताहिक जनचौपाल में सुनी आमजन की समस्याएं

बेमेतरा (समय दर्शन)। नवनियुक्त कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं ने सोमवार को कलेक्टोरेट परिसर द्वंद्व दृष्टि सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में जिले के दूर-दराज अंचलों से आए नागरिकों, ग्रामीणजनों एवं जनप्रतिनिधियों की मांगों, समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना। उन्होंने जनचौपाल में प्राप्त सभी आवेदनों का नियमानुसार त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए। कलेक्टर सुश्री ममगाईं ने जनचौपाल में उपस्थित आवेदकों से संवाद करते हुए कहा कि जनदर्शन शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का प्रभावी माध्यम है, जहां आम नागरिक अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के समक्ष रख सकता है। उन्होंने प्रत्येक आवेदन को बारी-बारी से स्वयं प्राप्त कर आवेदकों को उनके प्रकरणों की प्रक्रिया, नियमानुसार समाधान एवं समय-सीमा के संबंध में अवगत कराया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर गंभीरता से लेकर समयबद्ध निराकरण किया जाए, ताकि आमजन को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। जनचौपाल में कुल 36 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें प्रमुख रूप से धान खरीदी, राजस्व प्रकरण, प्रधानमंत्री आवास योजना, पर्यावरण संरक्षण, फसल क्षति, निर्माण अनुमति, सामाजिक भवन, खेल मैदान से अतिक्रमण हटाने एवं विभिन्न विकास कार्यों से संबंधित विषय शामिल रहे। जनचौपाल में ग्राम पंचायत जिया के रामकुमार वर्मा ने धान खरीदी केन्द्र जिया में प्रतिदिन धान खरीदी क्षमता बढ़ाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया। वार्ड क्रमांक 06 मोहभट्ठा निवासी तुलसी राम, महेश निर्मलकर एवं सुशीला ने धान विक्रय हेतु रिकार्ड दुरुस्त कराने के संबंध में आवेदन दिया। सहयोग संस्था बेमेतरा के अध्यक्ष डॉ. सुभाष चौबे ने मोहभट्ठा गार्डन के पास स्थित बरगद के वृक्ष के संरक्षण के संबंध में आवेदन देकर पर्यावरण संरक्षण की मांग रखी। ग्राम परपोड़ा निवासी लाला निषाद एवं गोपी राम निर्मलकर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अस्वीकृत आवेदन को स्वीकृत करने के संबंध में आवेदन दिया। वहीं ग्राम परपोड़ा के लगभग 14 पात्र हितग्राहियों ने पात्र होने के बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत दर्ज कराई। डॉ. अवधेश पटेल ने बेमेतरा जिले में केंद्र सरकार की ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर योजना को शीघ्र स्वीकृत कर क्रियान्वयन किए जाने हेतु आवेदन दिया। ग्राम पंचायत पतोरा के सरपंच ने निरस्त किए गए विकास कार्यों को पुन: प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया।

निगम आयुक्त ने नेहरू नगर जोन के विकास कार्यों का किया औचक निरीक्षण

भिलाई नगर (समय दर्शन)। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय द्वारा आज जोन-1 नेहरू नगर अंतर्गत विभिन्न वार्डों में संचालित विकास कार्यों का सघन निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने नवीन सीमेंटीकरण, डामरीकरण सड़क, तालाब, उद्यान और खेल मैदानों की वस्तुस्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्य समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण की शुरुआत वार्ड क्रमांक 6, संजय नगर से हुई, यहाँ स्थानीय नागरिकों द्वारा आवागमन की सुविधा हेतु सड़क निर्माण की लंबे समय से मांग की जा रही थी। जनहित को सर्वोपरि रखते हुए निगम द्वारा यहाँ नवीन डामरीकरण सड़क का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। आयुक्त ने सड़क का निरीक्षण करते हुए कहा कि इस मार्ग के बन जाने से स्थानीय निवासियों को धूल और कीचड़ से मुक्ति मिलेगी तथा सुगम आवागमन सुनिश्चित होगा। संजय नगर तालाब के निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने पाया कि तालाब के चारों ओर लगे चेकर टाइल्स (पेवर) कई स्थानों से उखड़ गए हैं। उन्होंने जोन आयुक्त को तत्काल इन टाइल्स को व्यवस्थित कराने एवं क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत के निर्देश दिए। साथ ही तालाब के मध्य बने चबूतरे का संधारण कर उसे बेहतर स्वरूप देने की बात कही। आयुक्त ने गुलमोहर उद्यान का भी अवलोकन किया। उद्यान परिसर में निर्मित भवन के पास वर्तमान में शेड निर्माण का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने संबंधित इंजीनियरों को शेड का कार्य शीघ्र पूर्ण करने तथा उद्यान के भीतर नियमित साफ-सफाई बनाए रखने के लिए निर्देशित किया। इसके पश्चात, समीप स्थित बैडमिंटन कोर्ट के निरीक्षण के दौरान उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से चैन लिंक फैंसिंग को व्यवस्थित और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए।

15वें वित्त की मूलभूत राशि के लिए पंचायत प्रतिनिधियों ने जिला मुख्यालय में किया आवाज बुलंद

महासमुंद(समय दर्शन)। 15 वें वित्त आयोग की वर्ष 2025-26 की मूलभूत राशि अभी तक नही मिलने से आक्रोशित सरपंच, जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य एक जुट होकर जनपद पंचायत महासमुंद में एकत्रित हुवे और रैली निकालकर जिला पंचायत पहुंचे जहां राशि आवंटन प्रस्ताव भेजने व राशि आवंटन संबंधित ज्ञापन जिला पंचायत सी ई ओ को सौंपा।

पंचायत प्रतिनिधियों की मांग है कि पंचायती राज संस्थाओ के सुदृढ़ संचालन हेतु पंचायतो में 15 वें वित्त आयोग की वर्ष 2025-26 की मूलभूत राशि प्रदाय नही किये जाने से पंचायत स्तर के अनेक कार्य ठप्प होने के कगार पर है।

इस राशि से पंचायत के अनेक कार्य संपादित होते थे,इसकी वजह से पंचायत में साफ- सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, मरम्मत एवं अन्य मूलभूत सेवाओं का संचालन प्रभावित हो रहा है।

जिससे पंचायती राज व्यवस्था की कार्य क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पंचायतों में 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) में स्वच्छता, सजावट, ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अन्य आवश्यक कार्य हेतु भी राशि नही है। पूर्व वर्षों में 15 वें वित्त की राशि 15 अगस्त या उससे पहले आवंटित हो जाती थी । सरपंच व जनपद सदस्यों का कहना है कि राशि आवंटन का प्रस्ताव शीघ्र नही भेजा गया तो मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे ।

आदित्य नगर में स्वास्थ्य शिविर, 100 से अधिक मरीजों को मिला नि:शुल्क परीक्षण व मार्गदर्शन

दुगेश्वर शिव मंदिर परिसर में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर – दंत और नेत्र रोगियों को मिला लाभ

स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता: शिविर में 40 दंत और 60 नेत्र मरीजों की हुई जांच

दुर्ग (समय दर्शन)। आदित्य नगर वार्ड 20 स्थित दुगेश्वर शिव मंदिर परिसर में नीलू महिला स्वसहायता समूह एवं ओम सत्यम शिक्षण एवं जन विकास समिति के संयुक्त तत्वावधान में स्वास्थ्य परीक्षण एवं मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य आम नागरिकों को घर-घर तक स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ना तथा बीमारियों के प्रारंभिक निदान के लिए जागरूक करना था।

शिविर में नगर के दंत चिकित्सक डॉ. अभिषेक खरे एवं डॉ. निकिता खरे द्वारा दंत रोगों से पीड़ित 40 मरीजों का परीक्षण किया गया। डॉक्टरों ने मरीजों को नियमित दंत-स्वच्छता, समय-समय पर परीक्षण और आवश्यक उपचार के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शन भी दिया।

नेत्र परीक्षण हेतु जिला चिकित्सालय के नेत्र विभाग के पूर्व नेत्र सहायक अधिकारी अरुण सिंह अपनी टीम के साथ उपस्थित रहे। उनकी टीम ने 60 लोगों की आंखों की जांच की, जिनमें से 3 मरीज दृष्टि-दोष से पीड़ित पाए गए। इन मरीजों को आगे की जांच और उपचार के लिए आवश्यक सलाह और प्रक्रिया की जानकारी प्रदान की गई।

शिविर में आने वाले नागरिकों के लिए नि:शुल्क परामर्श, जांच, दवाइयों की प्राथमिक सुविधा तथा बीमारियों की रोकथाम से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई गई। आयोजकों ने बताया कि ऐसे शिविरों के माध्यम से सामान्य लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ती है और कई गंभीर रोगों का समय रहते पता चल जाता है।

प्रायोजित इस स्वास्थ्य शिविर के सफल आयोजन में समूह की अध्यक्ष श्रीमती नीलू सिंह, संजय सिंह, के.एस. ओझा, बी.एन. झा, कृष्ण दत्त त्रिपाठी, अमर सिंह, ओम सत्यम शिक्षण एवं जन विकास समिति के अध्यक्ष सीताराम ठाकुर तथा सचिव दिलीप ठाकुर की उल्लेखनीय भूमिका रही। उपस्थित नागरिकों ने ऐसे शिविर नियमित रूप से आयोजित करने की मांग भी की।

राज्य स्तरीय रग्बी चैंपियनशिप में महासमुंद बालक एवं बालिका टीम बनीं विजेता

रग्बी चैंपियनशिप में महासमुंद को मिला दोनों वर्गों में विजेता का खिताब

महासमुन्द (समय दर्शन)। छत्तीसगढ़ रग्बी फुटबाल एसोसिएशन द्वारा 8 वीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय सब -जूनियर (बालक एवं बालिका) रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन दिनांक 28 दिसंबर को पंडित रवि शंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के शारीरिक शिक्षा विभाग खेल मैदान में किया गया। जिसमें राज्य भर से 15 बालक एवं बालिका टीम ने हिस्सा लिया। जिले की बालिका टीम ने अपने मैच जीतते हुए सेमीफाइनल में बिलासपुर को 29 अंकों से हराकर फ़ाइनल में प्रवेश किया जिसमें शिवानी, जिया व नंदनी ने शानदार गोल दाग कर टीम को जिताया। फाइनल मैच रायपुर एवं महासमुंद के मध्य खेला गया जिसमें महासमुंद ने 12 अंकों से जीत हासिल किया एवं प्रतियोगिता की विजेता टीम बनीं। बालक टीम ने सेमीफाइनल में महासमुंद ने बालोद को 10 अंकों से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फ़ाइनल मैच कोरबा एवं महासमुंद के मध्य खेला गया, जिसमें महासमुंद ने कोरबा को 07 अंकों से बढ़त हासिल कर विजेता का खिताब जीता। मैच में अजय एवं विजय ने शानदार गोल कर बेहतर प्रदर्शन किया। इस चैंपियनशिप में महासमुंद जिले की दोनो टीम ने विजेता का खिताब अपने नाम किया। बालक टीम कोच डॉ. सुनील कुमार भोई एवं जगदीश धीवर शामिल रहे। विजेता बालक टीम में आदित्य भारती, भूपेंद्र साहू, झलक ध्रुव, यथार्थ रात्रे, विनय तारक, पुष्पेंद्र यादव, मयंक साहू, मनीष कुर्रे, नैतिक शर्मा, गौरव सिंह, अजय प्रकाश साहू शामिल रहे। बालिका विजेता टीम में निशा ध्रुव, शिवानी बघेल, जिया खान, गीतांजलि साहू, प्रियंका साहू, मेघा चंद्राकर, नंदनी निषाद, जानवी चंद्राकर, सुहाना धीवर, श्वेता चंद्राकर, कंचन यादव, लोकेश्वरी चंद्राकर, कोच शुभांश शर्मा मैनेजर इंद्राणी भास्कर शामिल रहे। सभी खिलाड़ी अमावस, तुमगांव, अछोली, भोरिंग, बेलसोंडा आदि स्थानों में रहते हैं। रग्बी खेल का अभ्यास डॉ. सुनील कुमार भोई व्यायाम शिक्षक भोरिंग द्वारा विद्यालय, तुमगांव, बेलसोंडा एवं आसपास क्षेत्र में वरिष्ठ सीनियर खिलाड़ियों के सहयोग से अभ्यास कराया जाता हैं। तुमगांव एवं भोरिंग में विभिन्न खेलों का अभ्यास कराया जाता हैं, जिसमें रग्बी, सॉफ्टबॉल, बेसबॉल, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कुश्ती, टेबल टेनिस, खो खो, तलवारबाजी आदि शामिल हैं, जिससे माध्यम से खिलाड़ी बेहतर कौशल का प्रदर्शन कर राज्य एवं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भागीदारी कर राज्य स्तर पर पदक जीतने में सफल हो रहे हैं। प्रति वर्ष 150 खिलाड़ी राज्य स्तर पर एवं 40 खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व कर जिले को गौरवान्वित करते हैं। रग्बी चैंपियनशिप में दोनों टीम के विजेता बनने पर कलेक्टर विनय कुमार लंगेह, जिला शिक्षा अधिकारी विजय कुमार लहरे, खेल अधिकारी खेल एवं युवा कल्याण महासमुंद मनोज कुमार घृतलहरे, प्रियंका लवेश ढीढी, लीला लोकेश्वर साहू, सहायक क्रीड़ा अधिकारी अंजलि बरमाल, विकासखंड शिक्षा अधिकारी लीलाधर सिंहा, हिना ढालेन, हर्ष शर्मा, प्रीति त्रिभवन धीवर, लोचन साहू, रमेश साहू अंकित साहू, दीपेश साहू, असवन मिरि, हितेंद्र ढीढ़ी, आनंद टंडन, तेथिस चेलक, सतीश साहू, सावित्री साहू, समस्त शिक्षक स्टॉफ बेलसोंडा ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

विहिप प्रांतमंत्री पुणेंद्र सिन्हा का बसना में आत्मीय स्वागत

बसना (समय दर्शन)। विश्व हिन्दू परिषद के प्रांत मंत्री पुणेंद्र सिन्हा जी का बसना में जगदीशपुर ओवर ब्रीज के पास बसना विश्व हिन्दू परिषद के स्वयं सेवकों ने आत्मीय स्वागत किया गया। जिसमें बसना प्रखंड मे निवासरत विश्व हिन्दू परिषद, मातृशक्ति, बजरंग दल, दुर्गा वहिनी के कार्यकर्ताओं द्वारा आत्मीय स्वागत किया गया।

इस दौरान विहिप जिला मंत्री बसंत देवता,विहिप जिला सत्संग प्रमुख गणेश राम साहू, दुर्गा वहिनी जिला संयोजिका दामिनी पटेल, विहिप प्रखंड उपाध्यक्ष सविता वर्मन, विहिप प्रखंड मंत्री डॉ. भूपेन्द्र कुमार शर्मा,विहिप प्रखंड प्राचार प्रसार प्रमुख कृष्णा साहू, प्रखंड संयोजक बजरंग दल नीरज दास, प्रखंड सह संयोजक अनिल साव, दुर्गा वाहिनी प्रखंड संयोजिका ज्योति धृतलहरे, खण्ड मंत्री दीपक सेठ एवं साधु संत उपस्थित रहे।

प्रांत मंत्री भैया जी का नवीन दायित्व के बाद बसना प्रखंड मे प्रथम आगमन हुआ है जिनका स्वागत श्रीफल, अंगवस्त्र,माथे मे रोली लगाकर किया गया। प्रांत मंत्री भैया जी के साथ बालौदाबाजार के बजरंग दल जिला सह संयोजक दीपक साहू भी कार्यक्रम मे शामिल हुए। तद्पश्चात् सभी कार्यकर्ता भैया जी के साथ सिंघनपुर मे हो रहे विराट हिंदू सम्मेलन मे शामिल होने के लिए प्रस्थान किये। भैया जी के द्वारा विराट हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम मे संघ के विषय पर बौद्धिक दिया गया।

सिंघनपुर विराट हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम के समाप्ति उपरांत सिंघनपुर के माता सबरी मंदिर मे एक परिचय बैठक का आयोजन हुआ , जिसमें सर्व प्रथम सवरा समाज द्वारा अंगवस्त्र एवं मोमेंटो के साथ कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। सवरा समाज द्वारा आगामी 26 जनवरी को होने वाला धनुयात्रा कार्यक्रम मे शामिल होने के लिए सभी को आमंत्रित किया गया। विहिप के कार्यकर्ताओं के स्वागत हेतु सवरा समाज सिंघनपुर बहुत ही उत्सुक था। इस परिचय बैठक मे मातृशक्ति जिला संयोजक अनीता चौधरी, जिला सह संयोजक दुर्गा वहिनी ललिता सिदार , सरायपाली मातृशक्ति प्रखंड संयोजिका नमिता साहू, विराट हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम प्रभारी दिलीप साव, गिरधारी पटेल, सुशीला चौधरी शामिल हुए।

नगर पंचायत अध्यक्ष डॉ. खुशबू अग्रवाल ने वार्ड 08 में सुनी 'मन की बात' का 129वां संस्करण

बसना(समय दर्शन)। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 129वें एपिसोड का सामूहिक श्रवण आज बसना नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 08 में किया गया। इस अवसर पर बसना नगर पंचायत अध्यक्ष डॉ.खुशबू अग्रवाल स्वयं उपस्थित रहीं और उन्होंने वार्डवासियों के साथ प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी विचारों को ध्यानपूर्वक सुना।

कार्यक्रम में वार्ड पार्षद मुजम्मिल कादरी की गरिमामयी उपस्थिति रही। सामूहिक श्रवण कार्यक्रम में वार्ड की माताएं एवं बहनों की विशेष एवं उत्साहपूर्ण सहभागिता देखने को मिली, जिससे कार्यक्रम का वातावरण अनुशासित, सकारात्मक एवं प्रेरणास्पद बना रहा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 'मन की बात' के माध्यम से राष्ट्र निर्माण, सामाजिक एकता, स्वच्छता, आत्मनिर्भर भारत, महिला सशक्तिकरण तथा जनभागीदारी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा किए। उपस्थित नागरिकों ने प्रधानमंत्री जी के संदेशों को गंभीरता से सुना और उन्हें अपने दैनिक जीवन में आत्मसात करने का संकल्प लिया।

इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष डॉ. खुशबू अग्रवाल ने कहा कि 'मन की बात' कार्यक्रम आमजन को देश की सकारात्मक सोच से जोड़ने वाला सशक्त माध्यम है। यह कार्यक्रम समाज में जागरूकता, राष्ट्रप्रेम और सेवा भाव को सुदृढ़ करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के विचार हम सभी को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने तथा समाज और देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने की प्रेरणा देते हैं।

अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन अपनी 11सूत्रीय मांग को लेकर तीन दिवसीय हड़ताल पर

महासमुंद(समय दर्शन)। केन्द्र सरकार के समान कर्मचारियों एवं पेंशनरों को देय तिथि से महंगाई भत्ता लागू करने सहित 11 सूत्रीय मांग को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन आज से तीन दिवसीय (29 से 31 दिसंबर) हड़ताल पर चले गये । इनके हड़ताल पर चले जाने से शासकीय कार्यालय लगभग खाली पड़े है।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी- अधिकारी फेडरेशन आज से 11 सूत्रीय मांग को लेकर तीन दिवसीय (29 से 31 दिसंबर) हड़ताल पर चले गये है। कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन आज लौहिया चौक पर एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारे बाजी की। इनकी मांग है कि ड्ड एरियर्स की राशि कर्मचारियों के तक्क्न खाते मे समायोजित की जावे, सभी कर्मचारियों को चार स्तरीय समयमान वेतमान दिया जाये, लिपिको, शिक्षकों स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग त विभिन्न संवर्गो की वेतन विसंगतियों को दूर करने पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक किया

जाये आदि है। इनका कहना है कि अभी तीन दिवसीय हड़ताल पर है अगर इस बीच हमारी मांगो पर विचार नही किया गया तो आगे की रणनीति तैयार कर आरपार की लड़ाई लड़ी जायेगी ।

महासमुन्द के अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के जिला संयोजक का कहना है कि इस आंदोलन का नाम ही है मोदी की गांरटी । विजय बघेल जी जो चुनाव समिति के संचालन कर रहे थे उनके द्वारा घोषणा की गयी थी कि केन्द्र सरकार द्वारा जब जब मंहगाई भत्ता बढ़ाई जायेगी, तब- तब राज्य में भी बढायेगे , लेकिन प्रदेश सरकार सबके लिए काम कर रही है , केवल कर्मचारी- अधिकारियों को मोदी की गांरटी नही मिल रही है। जब तक मोदी की गारंटी नही मिलता ये आंदोलन चालू रहेगा ।

गौरतलब है कि इस हड़ताल में जिले के 40 कर्मचारी संगठन शामिल है, जिसमें चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से लेकर अपर कलेक्टर तक के अधिकारी शामिल है।

न्यायालय तहसीलदार तहसील पिपरिया जिला - कबीरधाम (छ.ग.)

ईकोर्ट क्र....... ब / 121 वर्ष 2025-26 ग्राम- गोरखपुर प.ह.नं. 10

// ईश्तहार //

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक गंगाराम पिता जुठेल चौहान निवासी ग्राम गोरखपुर पिपरिया तहसील पिपरिया जिला कबीरधाम द्वारा डुप्लीकेट किसान किताब जारी कराने हेतु आवेदन पेश किया गया है। ग्राम गोरखपुर प.ह.नं. 10 रा.नि.म. पिपरिया में स्थित भूमि ख.नं. 35/4 रकबा 0.020 हे. भूमि गंगाराम पिता जुठेल के नाम पर दर्ज है। उक्त भूमि का पूर्व में जारी ऋण पुस्तिका गुम हो जाने से डुप्लीकेट किसान-किताब जारी कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त आवेदित भूमि के डुप्लीकेट किसान-किताब जारी करने के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे नियत पेशी तिथि तक अपना दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईशहार आज दिनांक 19/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय के पदमुद्रा से जारी किया गया।

पेशी दिनांक 05/01/2026

मुहर

तहसीलदार
पिपरिया

काम बंद कलम बंद हड़ताल से प्रभावित हुआ सरकारी कामकाज

तीन दिवसीय हड़ताल के पहले दिन अधिकारी कर्मचारियों ने ने खोला मोर्चा

गरियाबंद (समय दर्शन)। छग प्रदेश अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले तीन दिवसीय कलम बंद हड़ताल गरियाबंद में भी शुरू हुई। मोदी की गारंटी लागू करने तीसरे चरण के फेडरेशन की हड़ताल का व्यापक असर सभी शासकीय कार्यालयों में देखने को मिला जहां अधिकारी कर्मचारियों ने कम बंद कर हड़ताल को अपना समर्थन दिया तथा नगर के गांधी मैदान में एकजुट होकर धरना दिया। फेडरेशन ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ने धरना दिया और सरकार पर मोदी की गारंटी पूरी न करने का आरोप लगाते हुए वादाखिलाफी करने की बात कही। फेडरेशन ने राज्य सरकार के खिलाफजमकर नारेबाजी की और मोदी की गारंटी पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने अपने संबोधन में कहा कि चुनाव पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी के तहत कर्मचारी अधिकारियों की मांगें पूरी करने का भरोसा दिया गया था, लेकिन सरकार बने दो साल बीत जाने के बाद भी मांगों पर कोई ठोस पहल या चर्चा नहीं की गई। पदाधिकारियों ने इसे वादाखिलाफी बताते हुए कहा कि यह आंदोलन सरकार को उसका वादा याद दिलाने के लिए किया जा रहा है। फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि यदि तीन दिनों के भीतर मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होती है, तो राज्य फेडरेशन से चर्चा कर उग्र आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। इस आंदोलन में जिले भर से हजारों की संख्या में अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए हैं।

तीन दिवसीय हड़ताल का व्यापक असर

इस तीन दिवसीय हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। राजस्व कार्य, पंचायतों का कामकाज सहित अन्य शासकीय सेवाएं पूरी तरह ठप हैं। वहीं जिला कार्यालय में भी हड़ताल का असर पड़ा है, जहां तीन दिनों तक कामकाज बंद रहेगी।वही फेडरेशन द्वारा केंद्र सरकार के सामान कर्मचारियों एवं पेंशनरों को देय तिथि से महंगाई भत्ता (ष्ठ) लागू किया जाए। ष्ठ एरियर्स की राशि कर्मचारियों के तक्क्ष्न खाते में समायोजित की जाए। सभी कर्मचारियों को चार स्तरीय समयमान वेतनमान दिया जाए। लिपिकों, शिक्षकों, स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग सहित विभिन्न संवर्गो की वेतन विसंगतियों को दूर करने पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए। प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए संपूर्ण सेवा लाभ दिया जाए। पंचायत सचिवों का शासकीयकरण किया जाए।सहायक शिक्षकों एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों को तृतीय समयमान वेतनमान दिया जाए। नगरीय निकाय के कर्मचारियों को नियमित मासिक वेतन एवं समयबद्ध पदोन्नति दिया जाए।

जिला शिक्षा अधिकारी का आकस्मिक निरीक्षण

दुर्ग (समय दर्शन)। जिला शिक्षा अधिकारी अरविन्द मिश्रा ने आज शासकीय प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालय नेवई, उतई, आदर्श नगर उतई, बोरीगारका, बोरीडीह, मातरोडीह, कातरो, रिसामा, अंडा तथा शासकीय हाई/हायर सेकंडरी विद्यालय उतई, कातरो, अंडा, मेडेसरा, ननकट्ठी का आकस्मिक निरीक्षण किया। प्राथमिक शाला उतई में प्रधानपाठक और सभी शिक्षक प्रार्थना स्थल पर सभी विद्यार्थियों को 22 तक के पहाड़ा का अभ्यास कराते मिले।

बच्चे पूरी ऊर्जा और ध्यान से दुहराते रहे। पहाड़ा के इस प्रकार के अभ्यास को देखकर डीईओ ने प्रधानपाठक दीप्ति रानी खोबरागड़े सहित सभी शिक्षको तथा कक्षा चौथी की हंसिका, मानवी और आर्यन को शाबाशी दी और उनकी प्रशंसा की। आदर्शनगर उतई और प्राथमिक शाला उतई में कक्षा खाली देखकर स्टाफरूम में बैठे प्रधान पाठक सहित सभी शिक्षकों के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें कक्षा खाली नहीं छोड़ने सख्त हिदायते दी।

शासकीय प्राथमिक शाला बोरीगारका में शिक्षक प्रहलाद सिन्हा को बच्चों के साथ मेट पर बैठकर अभ्यास कराते देख डीईओ ने उनके प्रयासों की प्रशंसा की। इसी तरह प्राथमिक शाला मातरोडीह में दो कार्यरत शिक्षकों में एक शिक्षक की ड्यूटी निर्वाचन में लगी है लेकिन वहां उपस्थित प्रधान पाठक रेखराम कोठारी कक्षा पहली से पांचवी तक के बच्चों को पढ़ाते मिले। कक्षा तीसरी के सभी बच्चो को धारा प्रवाह हिंदी वाचन, 15 तक पहाड़ा और बारह खड़ी में अभ्यस्त होने को देखते हुए डीईओ ने शिक्षक की पीठ थपथपाई और सभी बच्चों से ताली बजा उनका स्वागत किया।

डीईओ ने बताया कि एक शिक्षक होने के बावजूद रेखराम कोठारी का प्रयास बाकी ऐसे सभी शिक्षको के लिए भी प्रेरणास्पद है जो शिक्षक की कमी का बहाना अक्सर बनाया करते है। कातरो में बच्चो का स्तर कक्षा स्तरीय नही पाया गया। प्राथमिक शाला रिसामा में प्रधान पाठक नरेश ठाकुर की बिना सूचना अनुपस्थिति पर डीईओ ने तत्काल ठम्व् को कार्यवाही प्रस्तावित करने निर्देशित किया। शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालय उतई, कातरो, मेडेसरा, ननकट्ठी में बोर्ड परीक्षाओं हेतु डीईओ कार्यालय से भेजे गए प्रश्न बैंक, 5 वर्षो के बोर्ड के प्रश्न पत्रों को हल कराने, उन प्रश्नों के आधार पर टेस्ट परीक्षा आयोजित करने, मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं को विद्यार्थियो को देकर हुई त्रुटियों को सुधरवाने सहित प्रायोगिक परीक्षाओं की तैयारियों के संबंध में आवश्यक निर्देश भी दिए। डीईओ ने चिन्हांकित कमजोर बच्चों को सीमित पाठ्यक्रम से बोर्ड की तैयारी कराए जाने के निर्देश भी दिए।

ई डी की छापे से दहला महासमुन्द, रायपुर सहित महासमुन्द के दो ठिकानों पर दबिश

महासमुन्द (समय दर्शन)। उत्तर भारत की तरह छत्तीसगढ़ में पड़ रही कड़कड़ाती ठंड के बीच ई डी के छापे से सूबे के सियासत में फिर से एक बार गर्मी का उबाल आ गया है। सभी तरफई डी के छापे से सनसनी फैल गयी है। वहीं शोसल मीडिया में इस समाचार के व्यूवर्स काफी बढ़ गये है। पुष्ट सूत्रों से मिली से मिली जानकारी के अनुसार महासमुन्द जिला मुख्यालय के बसंत कालोनी स्थित जसबीर सिंह बग्गा के निवास में सुबह से ई डी ने दबिस दी है। रायपुर के हरमित खनूजा समेत उनके सहयोगियों के घरों एवं बंगलों एवं अन्य ठिकानो मे ई डी की रेड ने हड़कंप मच गया है।

आपको बता दें कि, भारत माला प्रोजेक्ट के घोटाले के तमाम संदिग्धों पर ई डी की बड़ी कार्यवाही देखने को मिल रहा है। अभी तक ई डी रिकार्ड खंगालने में जुटी है। समाचार लिखे जाने तक अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस संबंध में स्थानीय पुलिस को कानों-कान खबर तक नहीं। बिना किसी ठोस कारण के ई डी किसी पर इस तरह से रेड नहीं करती, जानकारों का मानना है कि, ई डी जहां भी इस तरह हाथ डालती हैं कुछ न कुछ हाथ ज़रूर आता है। अब देखना है इस मामले में ई डी को क्या सफलता मिलेगी।

डीएड योग्यताधारी शिक्षकों के लिए बीएड ब्रिज कोर्स कराने की मांग

डीएड प्रशिक्षित हो रहे है पदोन्नति से वंचित

कोरबा (समय दर्शन)। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री, पंकज अरोड़ा अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद, सचिव शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़, संचालक एससीईआरटी छत्तीसगढ़ व संचालक, लोक शिक्षण संचानालाय छत्तीसगढ़, को पत्र लिखकर शिक्षकों के प्रमोशन के लिए ष्ठ.श्वस्त्र. योग्यताधारी शिक्षकों के लिए क्चश्वस्त्र के 'ब्रिज कोर्स' हेतु प्रावधान बनाते हुए ब्रिज कोर्स कराने की मांग की है। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2019 में व्याख्याता पदोन्नति हेतु प्रशिक्षित स्नातकोत्तर का प्रावधान किया गया था, जिसके तहत बीएड या डीएड या समकक्ष शिक्षक भी पदोन्नति की पात्रता रखते थे, किन्तु एनसीटीई के प्रावधान के आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद केवल बीएड प्रशिक्षित शिक्षकों को पदोन्नति दी गई है, इससे हजारो डीएड प्रशिक्षित शिक्षक पदोन्नति से वंचित हुए है।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत चतुर्वेदी, प्रदेश संगठन मंत्री प्रमोद सिंह राजपूत, जिला अध्यक्ष मनोज चौबे, जिला सचिव नरेंद्र चंद्रा, मीडिया प्रभारी प्रदीप जायसवाल, कोषाध्यक्ष बुद्धेश्वर सोनवानी, जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र नायक, ब्लॉक अध्यक्ष उपेंद्र राठौर, रामशेखर पांडे, नागेंद्र मरावी, नंदकिशोर साहू ने कहा है कि छत्तीसगढ़ व अन्य प्रदेश के हजारों डीएड, डीपीई, बीटीआई या समकक्ष प्रशिक्षित शिक्षक प्राथमिक सहायक शिक्षक व पूर्व माध्यमिक शिक्षक पद पर कार्यरत हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय के वर्तमान निर्णय और एनसीटीई के दिशा-निर्देश के आलोक में प्राथमिक सहायक शिक्षकों व पूर्व माध्यमिक शिक्षकों के लिये प्रमोशन हेतु बीएड की अनिवार्यता की गई है जिससे हजारों शिक्षक प्रभावित होकर प्रमोशन से वंचित व पीड़ित हुए है, इससे बीएड ब्रिज कोर्स की प्रासंगिकता व अनिवार्यता महसूस किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन जिला कोरबा के जिला अध्यक्ष मनोज चौबे ने मांग करते हुए कहा है कि प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) व पूर्व माध्यमिक स्तर (कक्षा 6 से 8) में नियुक्त सभी सहायक शिक्षक, शिक्षक जो केवल डीएड या समकक्ष योग्यता रखते हैं, उन सभी के लिए एनसीटीई के नियमानुसार कोर्स संधारण कर अनिवार्य 6 माह के बीएड 'ब्रिज कोर्स' का प्रावधान बनाते हुए शासन स्तर से शीघ्र ब्रिज कोर्स प्रारम्भ किया जावे।प्रदेश के हजारों डीएड व समकक्ष प्रशिक्षित शिक्षकों के भविष्य को ध्यान रखते हुए विभागीय बीएड ब्रिज कोर्स कराने सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जावे।

संक्षिप्त-खबर

24 घण्टे के भीतर ग्राम देवरी में हुए हत्या के मामले में खुलासा करते हुए 11 आरोपी गिरफ्तार

गरियाबंद (समय दर्शन)। सोमवार को प्रार्थी गोपी राम तारक पिता विशेलाल तारक उम्र 58 वर्ष निवासी देवरी थाना राजिम जिला गरियाबंद छ.ग.द्वारा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थी के पुत्र मृतक हितेश्वर तारक उर्फ चंदु तारक को 28 दिसंबर के रात्रि करीबन 11 बजे गांव के करण साहू, नोहर विश्वकर्मा, विमलेश साहू, थानचंद साहू, सुनील साहू, शिव साहू, गजेन्द्र साहू, लक्ष्मीचंद सतनामी, भुरू उर्फ ओमप्रकाश सतनामी, उमाशंकर यादव, अक्षय साहू सभी निवासी देवरी थाना राजिम के द्वारा एक राय होकर पुरानी रंजिश को लेकर मृतक हितेश्वर तारक उर्फचंदु तारक को घर से जबरदस्ती घसिटते हुए कोपरा से बोरसी रोड के किनारे हत्या कर फेक दिया था।जिसकी रिपोर्ट पर धारा 332(ख), 296, 115(2), 351(3), 191(2), 191(3), 191, 103(1), बीएनएस 2023 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए गरियाबंद के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा थाना प्रभारी राजिम को हत्या के आरापियों की गिरफ्तार करने के निर्देश दिये गये।जिसके परिपालन में थाना प्रभारी द्वारा टीम गठित कर प्रार्थी के निशानदेही के आधार पर पुलिस टीम को रवाना किया।पुलिस टीम द्वारा हत्या के संदेही 11 आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पुछताछ किया गया। पुछताछ के दौरान सभी आरोपियों के द्वारा पृथक-पृथक मृतक हितेश्वर तारक उर्फचंदु तारक को लाठी-डण्डा व पत्थर से हत्या घटित करना स्वीकार किया गया। समस्त 11 आरोपियों के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से समक्ष गवाहों के विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।मृतक हितेश्वर तारक उर्फचंदु तारक एक आदतन अपराधी था।जिसके विरूद्ध थाना राजिम में गुण्डा बदमाश का फाईल दर्ज है।मृतक के द्वारा पूर्व में मारपीट, चोरी के कुल 8 अपराध एवं 9 प्रतिबंधात्मक कार्यवाही दर्ज है।

बालोद जिला में सड़क सुरक्षा को ले कर नए साल पर सबसे बड़ा संकल्प

बालोद (समय दर्शन)। नया साल नई उम्मीदों और खुशियों का संदेश लेकर आता है, लेकिन बालोद जिले में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाएँ हमें जगरूप होने के लिए मजबूर कर रही हैं। अधिकांश दुर्घटनाओं के पीछे तीन प्रमुख कारण सामने आ रहे हैं शराब सेवन कर वाहन चलाना और हेलमेट न पहनना और तेज रफ़्तार वाहन चलाना । ये तीनो ही लापरवाहियाँ सीधे तौर पर जानलेवा साबित हो रही हैं। शराब पीकर वाहन चलाना केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि स्वयं और दूसरों की जान को जोखिम में डालना है। नशे की हालत में चालक का संतुलन, दृष्टि और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। बालोद जिले में हुई कई गंभीर सड़क दुर्घटनाओं में यह तथ्य सामने आया है कि चालक नशे की हालत में था। ऐसे हादसों में निर्दोष लोग भी अपनी जान गंवा रहे हैं और कई परिवार हमेशा के लिए उजड़ रहे हैं।

दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट सबसे मजबूत सुरक्षा ढाल है। दुर्घटना के दौरान सिर में लगने वाली चोट जानलेवा हो सकती है और इसी तरह कुछ मिनट जल्दी पहुँचने की ज़िद तेज़ रफ़्तार वाहन चलाना सड़क दुर्घटनाओं का तीसरा और अत्यंत घातक कारण है। अधिक गति होने पर चालक वाहन पर नियंत्रण खो देता है और आपात स्थिति में ब्रेक लगाने का समय नहीं मिल पाता। बालोद जिले में कई दुर्घटनाएँ केवल तेज़ रफ़्तार के कारण हुई हैं,

यातायात पुलिस जिला बालोद का संदेश

卐नया साल हम सभी के जीवन में नई शुरुआत का प्रतीक है। मैं बालोद जिले के समस्त नागरिकों से विनम्र अपील करता हूँ कि सड़क पर निकलते समय अपनी और दूसरों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखें। यातायात प्रभारी रविशंकर पांडेय ने बताया कि यातायात पुलिस द्वारा नियमों के पालन हेतु लगातार कार्यवाही एवं जागरूकता अभियान चला रही है, लेकिन सड़क सुरक्षा तभी संभव है जब आम नागरिक अपनी जिम्मेदारी स्वयं समझे। अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने न दें और युवा वर्ग तेज रफ्तार व मोबाइल फेन के उपयोग से परहेज करें

धान खरीदी की व्यवस्था से किसान हुए संतुष्ट

दुर्ग (समय दर्शन)। राज्य सरकार की सुचारू, पारदर्शी और किसान हितैषी नीति के कारण जिले में धान खरीदी में तेजी आ रही है। धान खरीदी को आसान बनाने की दिशा में राज्य सरकार की निर्णायक कदम से धान विक्रय की प्रक्रिया सरल हुई है। जिसके तहत अब दिन-रात कभी भी मोबाईल एप तुंहर टोकन के माध्यम से किसानों को धान बेचने के लिए टोकन मिलने लगा है। किसानों के लिए यह बड़ी सहुलियत है कि उनके लिए तुंहर टोकन एप अब 24 घंटे उपलब्ध है। अब मोबाईल एप से टोकन काटने के लिए किसी निर्धारित समय की बाध्यता नही है। धान बेचने के बाद त्वरित भुगतान का किसानों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सरकार की व्यवस्था से प्रभावित होकर किसान अपनी उपज बेचने टोकन प्राप्त निर्धारित तिथि अनुसार पहुंच रहे हैं। जिले में अब तक 63,749.45 लाख रूपए की लागत से 2,68,901.52 मे. टन धान की खरीदी हो चुकी है। समय पर भुगतान राशि मिलने पर 50718 किसान लाभान्वित हुए हैं।

संत बाबा गुरुघासीदास ने मानवता का संदेश दिया-अशोक साहू

ग्राम रेंगाकठेरा में गुरु घासीदास जयंती मनाई गई

रानीतराई (समय दर्शन)। सतनामी समाज रेंगाकठेरा के तत्वाधान में परमपुज्य सदगुरु घासीदासजी की 269वी जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाया गया।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भूपेश बघेल (पूर्व मुख्यमंत्री)के प्रतिनिधि अशोक साहू पूर्व उपाध्यक्ष ज़िप दुर्ग थे, अध्यक्षता ममता राजू मेश्राम सरपंच ने की, विशेष अतिथि राजेश ठाकुर ब्लॉक अध्यक्ष, नोमिन ठाकुर सदस्य जिप दुर्ग, रश्मि भेदप्रकाश वर्मा(जनपद सदस्य पाटन), ईश्वरदयाल वर्मा समाजसेवी, राजेंद्र बघेल समाजसेवी, कमलेश नेताम कोषाध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस, सुलोचना चंदनीहा सरपंच डिडगा, प्रियालता महिपाल, सरपंच, औसर राधेकृष्ण यादव उपसरपंच ने बाबा गुरुघासीदास के तेलचित्र में माल्यार्पण, जोड़ा जैतखाम की पूजा अर्चना कर क्षेत्रवासियों की सुख, समृद्धि, खुशहाली, समरसता की मंगलकामना किए।

मुख्य अतिथि अशोक साहू ने कहा कि गुरू घासीदास जी के संदेश मनखे-मनखे एक बरोबर के महान विचार के कारण आज मानव समाज में विभिन्न मतावलंबियों के बीच आपसी मतभेद के बदले सौहार्द की भावना बढ़ी है तथा उनके महान विचारों में चलकर समस्त मानव समाज की सेवा करना ही सच्चे अर्थों में गुरू घासीदास जयंती मनाना सार्थक होगा। जनपद सदस्य रश्मि वर्मा ने पंथी गीत की प्रस्तुति देते हुए बताया हमें ानवता, समानता, सत्य, अहिंसा के सिद्धांत पर चलकर आने वाली पीढ़ी को संदेश देने की आवश्यकता है। समाजसेवी राजेंद्र बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विगत पांच वर्षों तक बाबा जी सिद्धांतों को आधार मानते हुए छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा की।वर्तमान में कई ढोंगी बाबा छत्तीसगढ़ को लूटकर कटोरा पकड़ाने की रीति पर चल रही है, ऐसे साधु सन्यासी बाबा से सावधान रहने की जरूरत है। कार्यक्रम में पंथी गीत एवं रात्रि में छत्तीसगढ़ी भावलोक नृत्य रिकार्डिंग डान्स परिवार दौना भानपूरी(बालोद)की अनुपम प्रस्तुति दी। जयंती समारोह में संतोष पटेल पूर्व सरपंच, तेजराम साहू, कमलेश वर्मा, दीनदयाल बांधे, दयालु बांधे, उदयकरण बिजौरा, मुकेश वर्मा, गोपी बांधे, अंकेश महिपाल, भेदप्रकाश वर्मा, बृजलाल चंदनिहा, भूपेंद्र बांधे, शत्रुहन चतुर्वेदी, बोधन बांधे, पवन चतुर्वेदी, डुमन राम, ईश्वर, लालचंद, योगेश बांधे सतनामी समाज एवं ग्रामवासी उपस्थित थे।

कलेक्टर महोबे की अध्यक्षता में जिले में जनगणना 2027 की तैयारी के संबंध में एक दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न

जांजगीर-चांपा(समय दर्शन)। कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जनगणना 2027 की तैयारी के संबंध में एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने प्रशिक्षण में अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्रशिक्षण को अत्यंत गंभीरता से लें और जनगणना के दौरान संभावित समस्याओं के संबंध में प्रशिक्षकों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचा जा सके। प्रशिक्षण के दौरान जनगणना निदेशालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के नोडल अधिकारी ने जानकारी दी कि जनगणना 2027 के लिए जनगणना निदेशालय द्वारा तहसीलवार सॉफ्ट फाइल उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें प्रत्येक राजस्व ग्राम एवं नगर को पूर्व में सत्यापित मानचित्र के अनुरूप दर्शाया गया है। इन सॉफ्ट फाइलों की तहसील कार्यालय स्तर पर सूक्ष्म जांच की जाएगी। यदि किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है, तो गूगल अर्थ प्रो के माध्यम से ग्रामों की सीमाओं को सुसंगत कर संशोधित शेप फाइल जनगणना निदेशालय को प्रेषित की जाएगी। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को गूगल अर्थ प्रो के उपयोग से संबंधित तकनीकी जानकारी पीपीटी के माध्यम से दी गई। इस अवसर पर जनगणना निदेशालय के अधिकारियों द्वारा उपस्थित जनगणना चार्ज अधिकारियों की शंकाओं का समाधान भी किया गया।

1 फरवरी को राजिम कुंभ कल्प का होगा भव्य शुभारंभ

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री, विभागीय सचिव, विधायक, संभागायुक्त कावरे एवं कलेक्टर उइके ने राजिम कुंभ कल्प आयोजन के संबंध में ली अधिकारियों की बैठक

गरियाबंद (समय दर्शन)। राजिम कुंभ कल्प 2026 के आयोजन के संबंध में आज महत्वपूर्ण बैठक राजिम के सर्किट हाउस में सम्पन्न हुई।बैठक में पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल, विभागीय सचिव अविनाश चंपावत, विधायक रोहित साहू, राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष चंदूलाल साहू, पूर्व विधायक संतोष उपाध्याय, रायपुर संभाग आयुक्त महादेव कावरे, गरियाबंद कलेक्टर बीएस उइके, धमतरी कलेक्टर अविनाश मिश्रा, धमतरी एवं रायपुर सहित गरियाबंद जिले के वरिष्ठ अधिकारीगण शामिल हुए। बैठक में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी राजिम कुंभ कल्प मेला भव्य तरीके से आयोजित करने के संबंध में विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।

पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि इस बार भी शासन के मंशानुरूप राजिम कुंभ कल्प मेला भव्य रूप से मनाया जाएगा। धार्मिक रीति रिवाजो के परंपरा पर प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले सन्त, महात्मा एवं आगंतुको के लिए इस वर्ष मेला स्मरणीय हो, अधिकारी का योगदान सर्वोपरि है अपने लगन और पूर्ण निष्ठा के साथ अधिकारी मेला को भव्यता का मूर्त रूप दे।विधायक रोहित साहू ने दुकान के आबंटन राशि के संबंध में राशि बढ़ोतरी न कर पूर्ववत रखने की मांग की। इसके साथ ही मेला स्थल में मेलार्थियों के लिए सभी सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। वहां पर मुख्य मंच बनाए जाएंगे। साथ ही दुकान, विभागीय स्टॉल एवं मीना बाजार भी लगाए जाएंगे। लोगों की सुविधा के लिए वृहद स्तर पर पार्किंग भी बनाए जाएंगे।बैठक में संभाग आयुक्त श्री कावरे एवं कलेक्टर श्री उइके ने राजिम कुंभ कल्प की तैयारी के संबंध में समीक्षा करते हुए टेंडर सहित सभी कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए।संभाग आयुक्त श्री कावरे ने रायपुर, धमतरी सहित गरियाबंद जिले के अधिकारियों को मेला के संबंध में समन्वय कर सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। साथ ही कलेक्टर श्री उइके ने जिले के अधिकारियों को मेला के संबंध में दिए गए दायित्वों को तत्परता के साथ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इस दौरान बैठक में वनमण्डलाधिकारी शशिगानंदन के. जिला पंचायत सीईओ प्रखर चंद्राकर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र चन्द्राकर, अपर कलेक्टर पवन प्रेमी, उप संचालक संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग प्रतापचंद पारख, एसडीएम राजिम विशाल महाराणा, जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता एस.के. बर्मन, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता रामेश्वर सिंह, पीएचई के कार्यपालन अभियंता विप्लव घृतलहरे, सहित वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे।

स्वामित्वधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक रोहित खड़तकर द्वारा समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स ग्राम छाटा, पोस्ट देवादा, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.) 491111 से मुद्रित कर बी-4, प्रेस काम्प्लेक्स, इंदिरा मार्केट, दुर्ग छ.ग. 491001 से प्रकाशित। संपादक :- रोहित खड़तकर,
समाचार संपादक : दामोदर राव, फोन नं.-0788-4051213, मो. 9827104452, रायपुर कार्यालय:-0771-4218364, ईमेल - samay.darshan191@gmail.com पं. क्र. CHHHIN/2011/41517 डाक पंजीयन क्रमांक छ.ग./दुर्ग/61/2024-26